मार्गशीर्ष कृष्णा - 13 ■ संवत 2081 ■ वर्ष - 20 ■ अंक - 124 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » गुरुवार » 28-11-2024 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 हिंदू नेता की रिहाई तक बांग्लादेशियों को वीजा जारी न किया जाए : अधिकारी

6 जलवायु परिवर्तन के खतरों से बच्चों को बचाएं

7 अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ 'महावतार नरसिहा' का प्रीमियर

फर्स्ट टेक

पारिवार अदालत ने धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के बीच तलाक को मंजूरी दी

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु की एक पारिवार अदालत ने बुधवार को अभिनेता धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के बीच तलाक को मंजूरी दे दी। फिल्म निर्देशक कस्तूरीराजा के बेटे धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने 18 नवंबर 2004 को अपने दोनों परिवारों के आशीर्वाद से विवाह किया। इस दंपती के दो बेटे हैं। शादी के 18 साल बाद नवंबर 2022 में उन्होंने औपचारिक रूप से एक-दूसरे से अलग रहने की घोषणा की। उसके बाद वे कानूनी रूप से एक-दूसरे से अलग होने के लिए परिवार अदालत गये और परस्पर सहमति से तलाक का आवेदन दिया। इस साल 21 नवंबर को वे पारिवार अदालत की न्यायाधीश सुभादेवी के सामने पेश हुए, जिन्होंने बंद कमरे में सुनवाई की। हालांकि, वे अलग होने पर अड़े रहे। इसके बाद न्यायाधीश ने बुधवार को उनके बीच तलाक को मंजूरी दे दी।

सरकार ने 6.69 लाख सिम कार्ड, 1.32 लाख आईएमईआई ब्लॉक किए

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र ने देश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा बताए गए 6.69 लाख सिम कार्ड और 1.32 लाख अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबर ब्लॉक किए हैं। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा को दी गई। गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने विदेशों से आने वाली ऐसी कॉल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है जिसमें भारतीय नंबर प्रदर्शित होते हैं। ऐसी कॉल से प्रतीत होता है कि वे भारत से ही की गयी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कॉल को ब्लॉक करने के लिए टीएसपी को निर्देश जारी किए गए हैं।

म्यामांर के सैन्य शासन प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध

हेग/एपी। अंतरराष्ट्रीय अपराधिक अदालत के मुख्य अभियोजक ने बुधवार को न्यायाधीशों से म्यामांर के रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए देश के सैन्य शासन प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग पर रोहिंग्याओं के निर्वासन और उत्पीड़न के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने 2021 में तख्तापलट के जरिये निर्वाचित नेता आंग सान सू ची से सत्ता हथिया ली थी।

सूर्यास्त 27-11-2024 5:50 बजे	सूर्योदय 28-11-2024 6:25 बजे
BSE 80,234.08 (+230.02)	NSE 24,274.90 (+80.40)
सोना 7,981 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 90,517 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

माया-जाल

बोलो कब छूटी है किनसे,
यूं झटपट दुनियावी माया।
मायावी बन बैठे त्यागी,
सच में उन सबने भरमाया।
माया की पोल खुली जिसकी,
वो बिना बात ही गरमाया।
माया का मायाजाल देख,
हर मायापति भी शरमाया।

हिंद-प्रशांत को व्यापक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की जरूरत : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रोम/भाषा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने क्वाड के उभार को एक उल्लेखनीय घटनाक्रम करार देते हुए कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र नए संबंधों और साझेदारी समेत महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है।

जयशंकर ने मंगलवार को इटली के शहर फ्यूजी में हिंद-प्रशांत भागीदारों के साथ जी7 विदेश मंत्रियों के सत्र में कहा, सामूहिक प्रयासों के युग में, हिंद-प्रशांत को व्यावहारिक समाधान, चतुर कूटनीति, अधिक समायोजन व अधिक स्वतंत्र वार्ता की आवश्यकता होगी। जी7 इसमें भागीदार हो सकता है। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का एक प्रमुख समूह है।

जयशंकर जी7 के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24-26 नवंबर तक आधिकारिक यात्रा पर इटली में थे। भारत को जी7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था।

जयशंकर ने सत्र के बाद 'एक्स' पर लिखा, क्वाड का उभार एक उल्लेखनीय घटनाक्रम रहा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज व्यापक सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, अधिक संसाधनों समेत छह प्रमुख आवश्यकताओं का उल्लेख किया।

'सनातन धर्म रक्षा बोर्ड' के गठन संबंधी याचिका पर गौर करने से अदालत का इंकार

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 'सनातन धर्म रक्षा बोर्ड' के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अधिकारियों को इस तरह का बोर्ड गठित करने का निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि यह मुद्दा नीतिगत क्षेत्र में आता है।

पीठ ने याचिकाकर्ता को इसके बजाय सरकार से संपर्क करने को कहा। पीठ ने कहा, '' आपको सरकार के पास जाना होगा। हम ऐसा नहीं करते। वे (सांसद) इसे संसद में उठाएंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते कि ट्रस्ट बनाएं।''

पीएम विश्वकर्मा योजना को मौजूदा स्वरूप में नहीं लागू करेगा तमिलनाडु : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को पत्र लिखकर सूचित किया कि राज्य सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करेगी।

स्टालिन ने मांझी को लिखे पत्र में कहा कि तमिलनाडु ने कारीगरों के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित एक अधिक समावेशी और व्यापक योजना तैयार करने का फैसला किया है, जो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती है।

मुख्यमंत्री ने इस साल चार जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे अपने पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि तमिलनाडु ने विश्वकर्मा योजना में संशोधन की मांग की थी।

इसके साथ ही उन्होंने इस योजना का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु में एक समिति गठित किए जाने का भी उल्लेख किया। दरअसल राज्य सरकार को इस बात की चिंता थी कि यह पहल 'जाति-आधारित व्यवसाय' की व्यवस्था को मजबूत करती है।

इस समिति ने केंद्र की योजना में संशोधन की सिफारिश की थी और इसे प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान में भी लाया गया था।

हालांकि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) विभाग की ओर से 15 मार्च को आए जवाब में राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधनों का कोई उल्लेख नहीं था।

स्टालिन ने कहा, ''ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन को उसके मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढ़ाएगी।''

इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन रोका

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इस्लामाबाद/भाषा। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने बुधवार को औपचारिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया और इसके लिए आधी रात को की गई अधिकारियों की कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

इससे पहले खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दावा किया था कि सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई हिंसक झड़पों में सैंकड़ों लोगों की मौत हुई है।

इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व करने वालीं खान की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के ठिकाने के बारे में चिंताओं के बीच पार्टी ने कहा कि वे दोनों खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद के पास मनसेहरा शहर में हैं।

मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में करेंगे गंगा पूजन

प्रयागराज/एजेन्सी। संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल शुरु होने वाले महाकुंभ 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 दिसंबर को गंगा पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और मां गंगा का पूजन करेंगे। उन्होने निर्देश दिए कि गंगा को पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जनसहयोग को प्राथमिकता दी जाए। महाकुम्भ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में

आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई में 10 लोग गिरफ्तार

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से की गई व्यापक कार्रवाई के दौरान बुधवार को आतंकी समूहों से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकी समूहों को रसद और वित्तीय मदद प्रदान करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा मल्हार, बानी और बिलावर के ऊपरी इलाकों के अलावा काना चक, हरिया चक, स्प्राल पेन और चक वजीर लाहबजू के सीमावर्ती क्षेत्रों में 17 स्थानों पर संयुक्त रूप से व्यापक अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि मल्हार, बिलावर और बानी थानों में दर्ज आतंकी घटनाओं से संबंधित तीन प्राथमिकियों के सिलसिले में सवाधानी और योजनाबद्ध तरीके से की गई छापेमारी से आतंकी समूहों से जुड़े 10 लोगों की पहचान और गिरफ्तारी हुई।

संपादकीय नियंत्रण नहीं होने से बेलगाम है सोशल मीडिया : वैष्णव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने वाले मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है।

वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल में इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अरुण गोविल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के युग में रह रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रेस के पारंपरिक रूप जो कभी जवाबदेही और सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय जांच एवं नियंत्रण पर निर्भर थे, समय के साथ अब इसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता का मंच तो बन गया है लेकिन इस तरह की संपादकीय निगरानी नहीं होने से यह अनियंत्रित अभिव्यक्ति का स्थान भी बन गया है, जिसमें अक्सर अशोभनीय सामग्री शामिल होती है।

कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/एजेन्सी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में रस्साकस्सी के तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ हैं और मुख्यमंत्री के बारे में वह जो भी फैसला करेंगे उन्हें मंजूर है। शिंदे ने बुधवार को यहां ठाणे में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी और उनकी तरफ से सरकार के गठन में कोई बाधा नहीं है और वह मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पूरी तरह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। श्री शिंदे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टेलीफोन करअपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि वह मुख्यमंत्री को लेकर जो भी फैसला करेंगे वह उन्हें मंजूर है। श्री शिंदे के इस बयान के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सभी अटकलबाजियों पर विराम लग गया है।

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाला वाद दायर

जयपुर/भाषा। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक वाद स्थानीय अदालत में दायर किया गया है। अदालत ने बुधवार को वाद को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए तीन पक्षकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वादी के वकील ने मीडिया को यह जानकारी दी। वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता योगेश सिरोजा ने अजमेर में संवाददाताओं को बताया कि वाद पर दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई।

इजराइल और हिज्बुल्ला के बीच संघर्ष विराम शुरू, लेबनान के लोग अपने घरों की ओर लौट रहे

■ इजराइल ने कहा है कि अगर हिज्बुल्ला समझौते का पालन नहीं करता तो वह उस पर हमला करेगा।

यरुशलम/एपी। इजराइल और हिज्बुल्ला के बीच बुधवार को संघर्ष विराम शुरू हो गया। संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि अगर हिज्बुल्ला समझौते का पालन नहीं करता तो वह उस पर हमला करेगा।

इजराइली और लेबनानी सेना की चेतावनी के बावजूद क्षेत्र के लोग अपने सामान के साथ दक्षिणी लेबनान की ओर कार से वापस लौट रहे हैं। इजराइल और लेबनान की सेना ने क्षेत्र के निवासियों को अभी दक्षिणी लेबनान के कुछ क्षेत्रों में नहीं लौटने की चेतावनी दी थी। अगर यह संघर्ष विराम कायम रहा तो इससे इजराइल एवं हिज्बुल्ला के बीच 14 महीने से जारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। हिज्बुल्ला के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई ने सितंबर के मध्य में युद्ध का रूप ले लिया और चरमपंथी संगठन के संरक्षक ने ईरान और इजराइल को व्यापक संघर्ष में घसीटने की धमकी दी।

बेंगलूरु | गुरुवार | 28-11-2024 www.dakshinbharat.com /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अदाणी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग को लेकर बुधवार को राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें अदाणी मुद्दे, मणिपुर हिंसा, संभल हिंसा और दिल्ली में अपराध के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कुल 18 नोटिस मिले हैं। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। जी सी चंद्रशेखर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, नीरज डांगी और राजीव शुक्ला सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने अन्य प्राधिकरणों के साथ मिलीभगत से अदाणी समूह के कथित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं सहित अन्य कदाचारों की जांच के लिए जेपीसी के गठन के लिए नोटिस दिए थे। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तिरूचि शिवा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के पी संदोष कुमार ने मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे पर जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जॉन ब्रिटास, माकपा के ए ए रहीम, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के अब्दुल वहाब ने

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राजधानी दिल्ली में अपराध के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। सभापति धनखड़ ने सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए कहा कि सदस्य इन मुद्दों को अन्य प्रावधानों के तहत उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं इस बात पर जोर देता हूं कि यह सदन, जो वरिष्ठ जनों का सदन है, उच्च सदन है, राज्यों की परिषद है, उसे उन परंपराओं का पालन करना चाहिए जो स्थापित हो चुकी हैं। सभापति के निर्णय का सम्मान होना चाहिए, न कि वह मतभेद का कारण बने।''

धनखड़ ने कहा कि उन्होंने विस्तार से समझाया है कि क्यों इन परिस्थितियों में इन नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''दरअसल, मैंने सदन को विश्वास में लेते हुए यह अवगत कराया कि यदि आप नियम 267 के संदर्भ में इस सदन की यात्रा को देखें तो पिछले 30 वर्षों में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, इस नियम का उपयोग कभी भी दोहरे अंक में नहीं गया। और हर बार की पृष्ठभूमि में एक सामूहिक दृष्टिकोण, दलों के बीच संवाद और सभी पहलुओं पर विचार होता था।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए, मैं इन नोटिस को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।''

सभापति ने सदन के सदस्यों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक दिन पर, जो संविधान अंगीकरण के शताब्दी वर्ष के चौथे चरण का पहला दिन है, सदन में कामकाज का का स्तर बढ़ाएं। उन्होंने कहा, ''हम एक ऐसा माहौल बनाएं जो चर्चा, संवाद, विमर्श और नियमों के पालन के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करे।'' उन्होंने कहा कि सदस्यों को इन सभी मुद्दों को नियमों के अनुसार उठाने के लिए अवसर मिलेगा क्योंकि नियमों में प्रावधान है कि इन मुद्दों को किसी न किसी रूप में प्रस्तावों के माध्यम से उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ''इसलिए इन नोटिसों को अस्वीकार किया जा रहा है।''

इसके तत्काल बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया। इससे पहले कि हंगामा और तेज होता, धनखड़ ने 11 बजकर 11 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा, जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो सभापति ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने स्थानों पर बैठे रहें और व्यवस्था बनाए रखें ताकि सूचीबद्ध कामकाज निपटाया जा सके। इसके बावजूद कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा करते रहे।

तेलंगाना की जनता कांग्रेस सरकार से तंग आ चुकी है, भाजपा की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि तेलंगाना की जनता वहां की कांग्रेस सरकार से तंग आ चुकी है और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कुशासन की भयानक यादें अब भी उनके मन में ताजा हैं, लिहाजा वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है।

प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ एक बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''तेलंगाना भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई।'' उन्होंने कहा, ''राज्य में हमारी पार्टी की उपस्थिति तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के लोग पहले ही कांग्रेस से तंग आ चुके हैं और बीआरएस कुशासन की भयानक यादें हैं। वे बड़ी उम्मीद से भाजपा की ओर देख रहे हैं।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा, ''हमारे कार्यकर्ता विकास के एजेंडे पर विस्तार से काम करते रहेंगे।'' प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वालों में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार तथा वरिष्ठ नेता के लक्ष्मण सहित कई सांसद और विधायक शामिल थे।

पिछले साल हुए तेलंगाना चुनाव में राज्य की 119 सदस्यीय विधानसभा सीट में से कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर सरकार बनाई थी जबकि सत्तारूढ़ बीआरएस 39 सीट पर सिमट गई थी। तेलंगाना में भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आठ सीट जीती थी।

एकनाथ शिंदे ने डाले हथियार, महाराष्ट्र में भाजपा के मुख्यमंत्री का रास्ता हुआ साफ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद मोलभाव की स्थिति से वंचित रह गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपने हथियार डालते हुए कहा कि उनके उत्तराधिकारी के नाम पर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी जो भी निर्णय लेगी, वह उन्हें स्वीकार होगा।

शिंदे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आश्वासन दिया है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के हर फैसले का समर्थन करेंगे और इस प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आयेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया। ठाणे स्थित अपने

आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ''मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी (नरेन्द्र मोदी) और अमित शाह को फोन किया था और उनसे (मुख्यमंत्री पद पर) फैसला करने को कहा था। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जो भी निर्णय लेंगे, मैं उसका पालन करूंगा।'' उन्होंने कहा, ''हमारी शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को नामित करने के भाजपा के फैसले का पूरा समर्थन करेगी। हमारी तरफ से कोई अडंगा नहीं है।'' शिंदे ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि उनके नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को शानदार जीत हासिल करने के बावजूद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से वह निराश हैं। उन्होंने कहा, ''कोई नाराज नहीं है। हमने महायुति के रूप में काम किया है।'' यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने से वह निराश हैं, शिंदे ने कहा, ''ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल का समर्थन किया था।''

यह पूछे जाने पर कि नए मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री कौन होगा, शिंदे ने कहा, ''अमित भाई (शाह) के साथ दिल्ली में कल बैठक है और उसमें सभी संबंधित निर्णय लिए जाएंगे।'' उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में अगली सरकार बनाने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। शिंदे ने कहा, ''मैं इस प्रचंड जीत के लिए एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में विधानसभा के दौरान व्यापक प्रचार किया। उन्होंने कहा, ''मैं अगले दिन प्रचार अभियान शुरू करने से पहले 2-3 घंटे ही सोता था।''

दक्षिण मुंबई में बहुमंजिला आवासीय इमारत में आग लगी

महिला दमकलकर्मी समेत दो घायल : अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। दक्षिण मुंबई में बुधवार को 22 मंजिला एक आवासीय इमारत में आग लग गई जिसमें एक महिला दमकलकर्मी समेत दो लोग घायल हो गए। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों पर फंसे निवासियों को छत पर ले जाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि आग अपराह्न करीब 1.10 बजे डोंगरी इलाके में अंसारी हाइट्स इमारत की 14वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रसोई गैस सिलेंडर फटने से लगी और इमारत की 19वीं मंजिल तक फैल गई। उन्होंने कहा कि मुंबई दमकल विभाग के मांडवी केंद्र से संबद्ध दमकलकर्मी अंजलि अमोल जामदादे (35) को आग बुझाते समय दाहिने कंधे में चोट लग गई, वहीं नासिर मुनी अंसारी (49) नामक व्यक्ति 15 प्रतिशत तक झुलस गया। अधिकारियों ने कहा कि दोनों को भायखला में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। उन्होंने कहा कि 22-मंजिला इमारत में आग ऊपर के तलों तक फैल गई। शुरुआत में बीएमसी ने कहा था कि इमारत में 15 मंजिल हैं और आग 14वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगी। बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को एहतियातन छत पर पहुंचाया गया क्योंकि सीढ़ियों के पास धुआं भरा था।

अदाणी मामले पर नया कानूनी शिगूफा छोड़ा गया, एजेंसियों को जांच करनी चाहिए : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अदाणी समूह के मामले में 'मोदी तंत्र' ने बड़ा कानूनी शिगूफा छोड़ा है, जबकि देश की प्रमुख एजेंसियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि विपक्ष यह मुद्दा संसद में उठाना जारी रखेगा।

अदाणी समूह की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि अरबपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी का यह भी कहना है कि उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें मौद्रिक दंड लगाया जाना शामिल है। रमेश ने एक बयान में कहा, ''इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि 'मोदानी इकोसिस्टम' ने आज सुबह-सुबह एक बड़ा कानूनी शिगूफा छोड़ा है। ऐसे समय में जब उन्हें अन्य देशों में हो रही गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, और उन तंत्र को वे न तो डरा सकते और ही ख़त्म कर सकते हैं, तब 'मोदानी इकोसिस्टम' इनकार करके नुकसान की भरपाई का प्रयास कर रहा है।'' उन्होंने दावा किया कि यह हास्यास्पद प्रयास अमेरिकी एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकता। रमेश ने कहा, ''इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अमेरिका न्याय विभाग के आरोप में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गौतम एस अदाणी, सागर आर अदाणी और अन्य लोगों ने भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश करने, अधिकृत करने, (रिश्वत) देने और वादा करने की एक योजना तैयार की।''

उनका कहना है, ''कायदे से, ईडी, सीबीआई और सेबी को इन खुलासों के मद्देनजर सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए। भ्रष्ट राजनीतिक-व्यावसायिक गठजोड़ के औजार के रूप में कार्य करने के बजाय, उनका काम यह है कि वे राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाएं।'' उन्होंने कहा, ''यह हमारे संस्थानों और उनमें महत्वपूर्ण पदों पर बैठे भारतीयों के लिए अपने दायित्व को निभाने का समय है। इतिहास इस क्षण को न तो माफ़ करेगा और न ही भूलेगा।'' रमेश ने इस बात पर जोर दिया, ''जहां तक हमारी बात है, हम इन मुद्दों को संसद और लोगों के समक्ष उठाते रहेंगे।''

सरकार का इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहन पर सब्सिडी को आगे जारी रखने का फैसला

नई दिल्ली/भाषा। माल ढुलाई वाले इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के खरीदार सब्सिडी का लाभ उठाते रहेंगे। सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ऐसे वाहनों के लिए प्रोत्साहन के दूसरे चरण को आगे बढ़ा दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए सब्सिडी आवंटन पहले ही समाप्त हो चुका है और सात नवंबर तक 80,000 से अधिक ऐसे वाहनों का पंजीकरण हुआ है।

इसके अलावा, सब्सिडी राशि को 25,000 रुपए प्रति वाहन तक सीमित कर दिया गया है, जो एक अप्रैल से सात नवंबर, 2024 के बीच पंजीकृत 80,546 वाहनों के लिए 50,000 रुपए प्रति वाहन से आधी कर दी गई है। मंगलवार को प्रकाशित नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, आठ नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले 1,24,846 वाहन पहले चरण में 5,000 रुपए/किलोवाट घंटा से कम दर पर 2,500 रुपए/किलोवाट घंटा की सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।

फ्रांस के विमानन, रक्षा उद्योग भारत में कारखाना लगाने पर विचार करें: गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को फ्रांस के विमानन उद्योग से भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के अवसर तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार है। फिलहाल 1,500 विमानों का ऑर्डर है और इसके 2,000 तक जाने की क्षमता है।

गोयल ने फ्रांस के विदेश व्यापार सलाहकारों के एशिया-प्रशांत मंच को संबोधित करते हुए कहा, ''भारतीय कंपनियों ने 1,500 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है और उनके पास इसे 2,000 तक ले जाने का विकल्प है। यह फ्रांसीसी

कंपनियों के हित में होगा कि वे भारत में विनिर्माण संभावनाओं को देखें और विमानों तथा उसके रखरखाव, मरम्मत तथा अन्य संबंधित उद्योगों के कलपुर्जों के लिए भारत में अपनी बिक्री बढ़ाने पर विचार करें।'' भारतीय कंपनियों के विमानों के ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा फ्रांसीसी कंपनी एयरबस को गया है। भारत में 2014 में हवाई अड्डों की संख्या 75 थी जो अब बढ़कर 125 हो गई है और 2029 तक 75 और हवाई अड्डे चालू हो जायेंगे। गोयल ने कहा, ''यह उन कंपनियों के लिए बड़ा अवसर है जो हवाई अड्डों और अन्य संबंधित उद्योगों को विकसित करना चाहती हैं।''

मंत्री ने विश्व बाजारों के लिए रक्षा क्षेत्र में भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच संयुक्त उत्पादन साझेदारी का भी सुझाव दिया।

बजट सत्र तक बढ़ सकता है वक्फ समिति का कार्यकाल

नई दिल्ली/भाषा। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में बुधवार को हुई बैठक में सदस्यों ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति व्यक्त की। बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से निर्णय लिया गया कि समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह करेगी कि समिति का कार्यकाल अगले साल के बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाया जाए। समिति ने कार्यकाल बढ़ाने का कदम ऐसे समय उठाने का फैसला किया है जब हाल ही में पाल ने कहा था कि रिपोर्ट तैयार है। सरकार की तरफ से भी पहले कहा गया था कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक लाया जाएगा। पाल ने बैठक के बाद बुधवार को कहा कि सदस्यों की राय थी कि कई राज्यों के अधिकारियों को अभी बुलाया जाना है, ऐसे में समिति का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाए जाने का आग्रह किया जाए।

केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर आमंत्रित किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों को अपने आवास पर चाय पर आमंत्रित किया और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों को सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने और राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आज मैंने अपने इलाके के सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर बुलाया। उनसे उनके सुख-दुख की बात की। उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझा। वे हर दिन मुस्कुराते हुए हमारी सेवा करते हैं, हमारे इलाके को साफ-सुथरा रखते हैं। आप भी उन्हें अपने घर बुलाएं, उनके साथ समय बिताएं। जब हम सब एकसाथ मिलेंगे, तभी हमारा स्वच्छ और सुंदर दिल्ली का सपना पूरा होगा।''

मंगलवार को आप के स्थापना दिवस पर केजरीवाल ने पार्टी विधायकों और पार्षदों से सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर आमंत्रित करने को कहा था। केजरीवाल द्वारा आमंत्रित सफाई कर्मचारियों ने भी उनके इस कदम की सराहना की। सफाई कर्मचारी संजय ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, ''हमें खुशी है कि अब हमें समय पर वेतन मिल रहा है और एमसीडी चुनावों में आप की जीत के बाद हमारे बकाये का भुगतान हो गया है।''

राजकोषीय घाटा 4.75 प्रतिशत रहने का अनुमान, पूंजीगत व्यय घटेगा: रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बुधवार को कहा कि सरकार व्यय पर नियंत्रण रखकर वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 4.75 प्रतिशत पर रख पाने में सक्षम होगी, जो बजट लक्ष्य से 0.19 प्रतिशत कम है।

घरेलू रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सब्सिडी को छोड़कर राजस्व व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.12 प्रतिशत होगा, जो बजट अनुमान से कम है। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री और सार्वजनिक वित्त प्रमुख देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में सरकार का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 62,000 करोड़ रुपए कम रहेगा। हालांकि, पंत ने यह कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय अब भी एक साल पहले के मुकाबले 10.6 प्रतिशत अधिक रहेगा। सरकार ने शुरू में पूंजीगत व्यय में 17.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भले ही सरकारी पूंजीगत व्यय घटा है, लेकिन चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के मुकाबले पूंजीगत व्यय 3.21 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दो दशक का उच्चतम स्तर है।

एजेंसी ने कहा, ''वित्त वर्ष 2024-25 के पूंजीगत व्यय में वृद्धि अप्रैल-मई में हुए आम चुनावों से प्रभावित हुई और पहली छमाही में पूंजीगत व्यय सालाना आधार पर 15.42 प्रतिशत कम रहा। ऐसे में बजट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में पूंजीगत व्यय में 52.04 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, जो मुश्किल काम लगता है।''

इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि रेलवे और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अपने पूंजीगत व्यय आवंटन को पार कर जाएंगे।

भारत को वित्तीय संस्थानों के आकार, पैमाने को लेकर लंबी छलांग लगाने की जरूरत : डिप्टी गवर्नर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों के पैमाने और आकार के मामले में लंबी छलांग लगाने की जरूरत है।

उन्होंने पिछले सप्ताह यहां भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित 'वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) में केंद्रीय बैंकों के उच्चस्तरीय नीति सम्मेलन' में कहा, ''हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं, हम पाते हैं कि अतीत में शुरू किए गए नियामकीय विकास और नीतिगत उपायों से भारत में एक मजबूत वित्तीय प्रणाली का विकास हुआ है, जिसने कई संकट का सामना किया है। उन्होंने कहा, ''लेकिन हमारे देश के लिए जो लक्ष्य हैं, उसके लिए हमें वित्तीय संस्थानों के पैमाने और आकार में लंबी छलांग लगाने की जरूरत है।''

इससे इकाइयों और उनके उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम भी बढ़ने की आशंका है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि इसे देखते हुए, मजबूत संचालन व्यवस्था और प्रभावी जोखिम प्रबंधन दोहरे आधार बनने जा रहे हैं जो हमारे वित्तीय संस्थानों को चालू रखेंगे और उन्हें लगातार बढ़ने में मदद करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''व्यापक तौर पर, वर्ष 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा को अब भी एक जटिल और तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में वित्तीय संस्थानों की एक मजबूत नींव की आवश्यकता है।'' राव ने कहा कि बैंकों के अलावा, मौजूदा इकाइयों को परिसंपत्ति की अपनी बढ़ती जरूरतों को वित्तपोषित करने के लिए मजबूत पूंजी बाजारों तक आसान पहुंच की आवश्यकता होगी। साथ ही उन्हें मजबूत वित्तीय बाजारों तक पहुंच की जरूरत होगी जो उन्हें बही-खाते से संबंधित जोखिमों से बचाव करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, बढ़ती कर्ज जरूरतों को पूरा करने के लिए नई इकाइयों, उत्पादों और सेवाओं (निजी क्रेडिट) का आगमन होगा। राव ने कहा, ''इसीलिए, इन चुनौतियों से निपटने और नवोन्मेष की प्रक्रिया में बाधा डाले बिना वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए एक उपयुक्त नियामकीय प्रणाली स्थापित करनी होगी।'' उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे केंद्रीय बैंक कम हैं, जिन्हें आरबीआई जैसी व्यापक जिम्मेदारी मिली हुई है। डिप्टी गवर्नर ने कहा, ''आरबीआई एक पूर्ण सेवा वाला केंद्रीय बैंक है। इसका कार्यक्षेत्र मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन, विनियमन और पर्यवेक्षण, भुगतान प्रणाली, वित्तीय समावेश और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

राव ने कहा, ''इस बढ़ी जिम्मेदारी के बावजूद, आरबीआई के अस्तित्व के नौ शानदार दशक और एक नियामक तथा पर्यवेक्षक के रूप में 75 साल के अनुभव ने एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र की नींव बनाई है जो देश को अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है।''

जाति-धर्म के नाम पर मनुष्य को बांटने वाले विधर्मी हैं : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेल्लारी। यहां बेल्लारी धर्मक्षेत्र पालकों द्वारा आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मानव–घृणा करने वाले विधर्मियों से सावधान रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत बहुलतावाद का देश है। सर्वधर्म सद्भाव भारत की धरती है। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने आह्वान किया कि इसकी रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है उन्होंने बेल्लारी धर्मक्षेत्र के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया और धर्म संगठन द्वारा गरीब परिवारों को दिए गए मुफ्त मकान सौंपने के बाद कहा कि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। उन्होंने कहा कि प्रेम और मानवता ही सभी धर्मों का सार है। धर्म का अर्थ बहुत सरल है। जैसा कि बसवन्ना ने कहा था, दया धर्म का मूल है। जहां नफरत और ईर्ष्या है, वहां कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि नफरत से समाज टूट जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आइये अपने धर्म का पालन करें। हमारे संविधान का महान मूल्य सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इसका पालन करना स्वामी विवेकानन्द और संविधान के प्रति हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। मैं किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता। उन्होंने बताया कि मैं ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्धों से उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं हिंदुओं से करता हूं।

उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था ने पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, शूद्रों, दलितों और संपूर्ण स्त्री जाति को शिक्षा से वंचित कर दिया। हालांकि, हमारे संविधान ने उन सभी को जाति बंधनों से मुक्त किया और उन्हें शिक्षा प्रदान की। बासवन्ना ने 850 साल पहले यह कहकर जाति व्यवस्था को ललकारा था कि यह हमारा नहीं है, यह हमारा है। उन्होंने कहा, हालांकि, जाति आज भी नहीं गई है।

उन्होंने कहा कि ईसाई शिक्षक और ईसाई संगठन सभी धर्मों और जातियों के गरीबों को शिक्षित कर रहे हैं। यह समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक शिक्षा हो। सभी का मानना है कि ईश्वर एक है नाम अनेक हैं। बसवादी शरण ने कहा कि पैर स्तंभ है, शरीर मंदिर है और सिर कलश है, इसी कारण से उन्होंने कनकदास के केले की कहानी बताई जिससे यह संदेश फैला कि भगवान के बिना कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में अम्बेडकर का भाषण सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी को संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस मौके पर ईसाई धर्मगुरु पीटर मचाडो, मंत्री केजे जॉर्ज, केकेआर डीबी के अध्यक्ष अजय सिंह, विधायक भरत रेड्डी, नागेंद्र, अन्नपूर्णा तुकाराम और कई अन्य नेता मौजूद थे।

'मुडा' विवाद : लौटाई गई जमीन पर एक महिला ने जताया हक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। कर्नाटक में मुडा (एमयूडीए) जमीन आवंटन विवाद के बीच एक महिला ने मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या की पत्नी पार्वती बीएम द्वारा प्राधिकरण को लौटायी गयी जमीन पर दावा करते हुए दीवानी वाद दायर किया है। विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब जमुना ने स्थानीय अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करते हुए दावा किया कि मैसूरु के केसारे गांव में सर्वे नंबर 64 में तीन एकड़ और 16 गुंटा जमीन में उसे हिस्सा देने से मना कर दिया गया। इसका मतलब है कि जमुना ने उस जमीन पर हक जताया जिसे एमयूडीए ने पार्वती से लिया था।

केसारे की यह जमीन पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने कथित रूप से भेंट में दी थी। स्वामी ने देवराजू से यह जमीन खरीदी थी। जमुना देवराजू की भतीजी है। मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) ने केसारे में पार्वती से जो जमीन ली थी उसके बदले में उसने उन्हें पॉश क्षेत्र में 14 भूखंड आवंटित किये थे। इस सिलसिले में लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसमें आरोप लगाया गया था कि पार्वती को जो भूखंड दिये गये थे, वे उनसे ली गयी जमीन से अधिक मूल्य के थे।

जब कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्वती को भूखंड आवंटित किए जाने को लेकर आवाज उठायी और उन्होंने राज्यपाल एवं अदालत से संपर्क किया तब लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती, मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू के खिलाफ मामला दर्ज किया। जब जमीनों का यह लेन–देन विवादों में घिर गया तब पार्वती ने प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित भूखंड लौटा दिये।

जमुना ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि (केसारे की) उस जमीन में उसका भी हिस्सा है तब उसने चार माह पहले वाद दायर किया। जमुना के अनुसार यह जमीन मूल रूप से उसके पिता माइलारैया की थी। जमुना ने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद उसे अपने हिस्से के बारे में पता चला।

कांग्रेस आलाकमान से चर्चा कर कैबिनेट में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार : परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा आलाकमान से चर्चा के बाद निर्णय लेंगे।

उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना का संकेत देते हुए मंगलवार को कहा था कि कुछ मंत्रियों को उनके कार्यकाल के बारे में ''संदेश'' दिया गया है। इससे मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को और बल मिला है।

परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, ''मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मंत्रिमंडल में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से सलाह–मशविरा करेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे, यह परंपरा रही है। मुझे नहीं पता कि वह क्या निर्णय लेंगे। यह आलाकमान से चर्चा के बाद किया जाना चाहिए।''

शिवकुमार के बयान के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ''वह (शिवकुमार) पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने (कुछ मंत्रियों को) क्या संदेश भेजा है।'' उन्होंने मुसलमानों के मताधिकार को समाप्त करने संबंधी एक मठ के महंत की टिप्पणी से संबंधित सवाल पर कहा कि संविधान के विपरीत टिप्पणी करना उचित नहीं है और किसी को भी इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए तथा न ही इसके खिलाफ जाना चाहिए।

परमेश्वर ने कहा, ''संभवतः उन्होंने (महंत) संविधान के सिद्धांतों और हर समुदाय एवं धर्म के लिए इसमें दिए गए अधिकारों तथा अवसरों का ठीक से अध्ययन नहीं किया है। संविधान में यह स्पष्ट है।''

शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए तालुक स्तर के अस्पतालों में विशेष नवजात देखभाल इकाइयां स्थापित होंगी : स्वास्थ्य मंत्री

सिजेरियन सेक्शन की दर कम करने पर बल दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिम्मोग्गा। यहां स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडुराव ने कहा है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए तालुक स्तर के अस्पतालों में विशेष नवजात देखभाल इकाइयां (एसएनसीयू) स्थापित की जाएंगी। मंत्री, जिन्होंने बुधवार को शिम्मोग्गा में जिला स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा की, ने कहा कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और अधिकारियों को शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि केवल जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ हैं। तालुका स्तर के एमसीएच अस्पतालों से जिला स्तर के अस्पतालों तक बच्चों को ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए, तालुक स्तर पर मातृ एवं शिशु अस्पतालों में एसएनसीयू प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। इस संबंध में मंत्री दिनेश गुंडुराव ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त को निर्देश दिया है कि राज्य भर में जहां अधिक प्रसव हो रहे हैं, उन एमसीएच अस्पतालों की सूची तैयार करें और एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि कहां एसएनसीयू की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि 70 फीसदी सिजेरियन डिलीवरी निजी अस्पतालों में हो रही हैं। यह उचित नहीं है। सिजेरियन सेक्शन मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर असर डालता है। सिजेरियन रेट 20 प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में 70 फीसदी सिजेरियन किए जाते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह दर 35 फीसदी है। इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिजेरियन सेक्शन को कम से कम 50 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए। इस संबंध में मंत्री दिनेश गुंडुराव ने जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निजी अस्पतालों पर सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को अंधता मुक्त शिम्मोग्गा कार्यक्रम में हर तरह का सहयोग देने का निर्देश दिया और अधिकारियों को आंखों की जांच और मोतियाबिंद, शल्य चिकित्सा सहित मुफ्त चश्मा प्रदान करने वाली आशाकिरण योजना के साथ जिले में कार्यक्रम को लागू करने की सलाह दी। उन्होंने जनवरी महीने के भीतर शिम्मोग्गा जिले के सागर, होसानगर और शिम्मोग्गा ग्रामीण क्षेत्रों में तीन मोबाइल मोबाइल क्लीनिक प्रदान करने का वादा किया।

सागर और भद्रावती तालुक अस्पतालों को उन्नत किया जाएगा और अधिक उपयोगी उपचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भद्रावती में नये एमसीएच अस्पताल के निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण किया गया है। मंत्री दिनेश गुंडुराव ने कहा कि सरकार तालुक स्तर के अस्पतालों को अपग्रेड करने पर अधिक जोर देगी।

लॉकअप मौत मामले में चार पुलिसकर्मियों को सजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बुधवार को एसीसीएमए कोर्ट के 51वें अतिरिक्त न्यायाधीश ने एक संदिग्ध व्यक्ति की लॉकअप मौत के मामले में चार पुलिसकर्मियों को सात साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2016 को इंदिरानगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक मामले में शंका के आधार पर पुलिस द्वारा महेन्द्र राठौड़ को थाने में पकड़ कर लाया गया। पुलिस थाने में मौजूद हैड कांस्टेबल इजाज खान, कांस्टेबल केशव मूर्ति, मोहनराम और सिद्दप्पा ने पूछताछ के दौरान महेन्द्र की बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई के दौरान महेन्द्र की मौत हो गई। इस मामले की जांच सीआईडी पुलिस को सौंपी गई।

सीआईडी पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में पता चला कि चारों पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ित को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था जिससे उसकी मौत हो गई। वर्ष 2017 में चारों अभियुक्तों पर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के बाद बुधवार को एसीसीएमए कोर्ट के न्यायाधीश ने चारों को आईपीसी की धारा 304 के तहत सात साल की सजा और 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, वहीं आईपीसी की धारा 330 के तहत 5 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

बधाई

बुधवार को दिल्ली में एआईसीसी महासचिव प्रियांका वाड्रा से कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुलाकात की और उन्हें वायनाड से अभूतपूर्व अंतर से लोकसभा के लिए चुने जाने पर बधाई दी।

एमजीएम मलार हॉस्पिटल में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर के घुटने की सफल सर्जरी की गई

चेन्नई। स्थानीय अड्यार स्थित एमजीएम मलार हॉस्पिटल द्वारा कैमरून के 54 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर तथा केरल एफसी के पूर्व कोच रहे रिचर्ड टोवा के घुटने के प्रतिस्थापन की सफल सर्जरी की गई है। रिचर्ड टोवा पूर्व पेशेवर फुटबाल खिलाड़ी तथा कोच रहे हैं तथा खेल मैदान पर अपने असाधारण कौशल के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। रिचर्ड टोवा पिछले छः माह से घुटने के असहनीय दर्द से जूझ रहे थे जिसके कारण उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के कामों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हाल ही में इलाज के लिए एमजीएम हॉस्पिटल आए रिचर्ड टोवा का डॉक्टरों द्वारा गहन जांच की गई। हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा सलाहकार डॉक्टर नंदकुमार सुंदरम एवं उनकी टीम ने एक्सरे तथा नैदानिक आंकलन के उपरांत पाया कि रिचर्ड टोवा के घुटने के जोड़ों को गंभीर क्षति हुई है इस क्षति को कम करने के लिए उन्हें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी।

इस खिलाड़ी के घुटने की सफल सर्जरी करने वाले डॉ नंदकुमार सुंदरम ने कहा कि फुटबॉल खिलाड़ियों में घुटने की चोटों जैसे की एसीएल, एमसीएल और मेनिस्कस टियर की व्यापकता प्रभावी रोकथाम रणनीतियों के महत्व को रेखांकित करती है। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए घुटने के जोड़ का महत्व बहुत अधिक है। खेल की उच्च तीव्रता के साथ मिलकर छोटी और गंभीर दोनों तरह की चोटों का कारण बन सकती है जो खिलाड़ी के पूरे करियर को प्रभावित करती है।

'स्पर्श' आउटरीच कार्यक्रम में रक्षा पेंशनभोगियों को मिली राहत

बेंगलूरु। पीसीडीए, बेंगलूरु द्वारा संचालित 'स्पर्श' आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र 26 नवंबर को चोपड़ा ऑडिटोरियम में एएससी सेंटर (दक्षिण) के सहयोग से आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम रक्षा पेंशनभोगियों और रक्षा नागरिक पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण के लिए 26 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में डीएलसी 3.0 अभियान के तहत पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

इस अवसर पर रक्षा लेखा के अतिरिक्त महानियंत्रक, आईडीएएस आरके अरोड़ा मुख्य अतिथि थे। अरोड़ा ने रक्षा लेखा विभाग द्वारा शुरू की गई 'स्पर्श' पहल की विशेषताओं को गिनाया और आशा व्यक्त की कि कार्यक्रम में स्थापित शिकायत निवारण पीठों द्वारा पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक देशभर में 44 स्टेशनों पर स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीसीसीआई, एएससी सेंटर एवं कॉलेज मेजर जनरल एसएस अहलावत ने कहा कि यह आउटरीच कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों से सीधे जुड़ना है। उन्होंने सभी पेंशनभोगियों को प्रोत्साहित किया कि वे शिकायत निवारण बेंच पर डीएडी के अधिकारियों को अपनी समस्याएं विस्तार से बताएं, ताकि उचित समाधान मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रणाली को डिजिटल बनाने तथा इसे कहीं से भी सुलभ बनाने के लिए की गई पहल से सभी बिचौलिए समाप्त हो गए हैं, जो पहले मौजूद थे।

पीसीडीए, बेंगलूरु के नियंत्रक, आईडीएएस टी रामबाबू ने पेंशनभोगियों की सेवा के लिए प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के लिए 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पेंशनभोगियों की सहायता और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कर्नाटक के विभिन्न स्टेशनों पर स्पर्श सेवा केंद्र खोले गए हैं। उद्घाटन सत्र के बाद मुख्य अतिथि ने पेंशनरों और अधिकारियों के साथ बातचीत की।

तमिलनाडु में बारिश जारी, कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में खड़ी फसलें प्रभावित

चेन्नई। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में बुधवार को भी बारिश जारी रहने से यहां धान की फसल प्रभावित हुई। विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने राज्य सरकार से किसानों को उचित राहत प्रदान करने का आग्रह किया। तिरुवरूर, थिरुथुराईपोंडी, मुथुपेट्टई, मयिलादुथुराई और वेदारण्यम सहित कई स्थानों पर बारिश के कारण फसलें आंशिक रूप से और कई जगह पूरी तरह से जलमग्न हो गईं तथा किसानों के अनुमान के अनुसार कम से कम दो हजार एकड़ से अधिक भूमि पर तैयार खड़ी फसलें प्रभावित हुईं। इसके अलावा, नागपट्टिनम (वेदारण्यम) और विल्लुपुरम (मरक्कनमन) जिलों में नमक उत्पादन वाले बड़े क्षेत्र जलमग्न हो गए।

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने थिरुथुराईपोंडी (तिरुवरुर जिला) में 1,500 एकड़ धान की फसल प्रभावित होने की खबरों पर आश्चर्य व्यक्त किया और अधिकारियों द्वारा वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए जाने तथा द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार से किसानों को उचित राहत प्रदान करने की मांग की। किसान नेता पी. आर. पांडियन ने डेल्टा क्षेत्रों में नहरों और नदियों की उचित ढंग से सफाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। मंत्री टीआरबी राजा ने थिरुथुराईपोंडी में राहत शिविरों और क्षेत्र में जलमग्न फसलों का निरीक्षण किया, जबकि जिले के अधिकारियों ने भी प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया।

राज्य सिंचाई योजना के लिए अनुमति की मांग के साथ उपमुख्यमंत्री शिवकुमार की अपील

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की और एक अनुरोध पत्र सौंपा। शिवकुमार ने बुधवार को दिल्ली में प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और राज्य में महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने अनुरोध किया कि मेकेदातु परियोजना एक टिकाऊ पेयजल परियोजना है और इस परियोजना का कार्यान्वयन आवश्यक है। कृष्णा विवादित जल न्यायाधिकरण 2 के फैसले के अनुसार हमें अपने हिस्से के पानी का उपयोग करने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करनी होगी।

सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत

चेन्नई। ममल्लापुरम राजमार्ग पर बुधवार को एक तेज रफ्तार कार की टक्कर के कारण पांच महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि पांचों महिलाओं को उस समय कार ने टक्कर मार दी जब वे मवेशी चराने और खाना खाने के बाद सड़क पार करने का प्रयास कर रही थीं। उन्होंने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

गुलाबी नगरी को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रमुख शासन सचिव ने दिए सख्त निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। 'राइजिंग राजस्थान 2024' के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बुधवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की उपस्थिति में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जयपुर शहर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, कानून व्यवस्था, और यातायात प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्धता के साथ काम करने और सभी तैयारियों को शीघ्रता से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की प्रगति की जानकारी दी। प्रमुख शासन सचिव ने प्रत्येक विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए।

यादव ने स्वच्छता अभियान को 'राइजिंग राजस्थान 2024' की प्राथमिकता बताते हुए नगर निगम तथा जेडीए को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और पर्यटक स्थलों को विशेष रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जाए। शहरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी, सड़कों के किनारे हरियाली और प्रमुख चौकों को रोशनी और सजावट से सुसज्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजेश यादव ने पुलिस विभाग को शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'राइजिंग राजस्थान 2024' के दौरान आने वाले मेहमानों और प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उन्होंने यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और सड़कों पर सुचारु आवाजाही के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा।

प्रमुख सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'राइजिंग राजस्थान 2024' राजस्थान की प्रगति और विकास को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए हर विभाग को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनता को भी इन तैयारियों में शामिल करें ताकि एक सामूहिक प्रयास से राज्य की छवि और अधिक उज्ज्वल हो सके।

यादव ने कहा कि राजस्थान अपने आतिथ्य-सत्कार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि समिट में भाग लेने के लिए आने वाले ब्रांड एम्बेसेडर, निवेशकों एवं अन्य अतिथियों को सरल एवं सहज सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। उन्होंने उद्घाटन सत्र के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों, अतिथियों की बैठक व्यवस्था तथा अन्य तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को तैयारियों को अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर पुलिस आयुक्त, आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर,आयुक्त, नगर निगम, हेरिटेज, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल,अतिरिक्त आयुक्त, यातायात पुलिस,निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर विकास प्राधिकरण,शासन उप सचिव, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, सलाहकार, रीको विभाग, और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजेश यादव ने विश्वास जताया कि समर्पित प्रयासों और सही योजना के साथ 'राइजिंग राजस्थान 2024' का आयोजन न केवल राज्य के नागरिकों को गर्व महसूस कराएगा बल्कि देश और विदेश से आने वाले मेहमानों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा।

राजस्थान फोन टैपिंग केस

मंत्री जोगाराम पटेल बोले- अभी एक 'मछली' फंसी है, कई मगरमच्छ भी आएंगे कानूनी दायरे में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। राजस्थान के संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल बुधवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई किए। इस जनसुनवाई में दूरदराज के ग्रामीण भी पहुंचे और अपनी समस्याओं को बताया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी चुनाव हुए और उपचुनाव में सातों विधानसभा सीटों में से पांच बीजेपी ने जीती। इसलिए मैं वहां के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए कार्यों और बजट की घोषणाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का संकल्प और उनकी क्रियान्विति पर मोहर लगाई है। वहीं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि एक लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं, भर्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह विषय सरकार के सम्मुख विचाराधीन है और चूंकि यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए इस पर ज्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। न्यायालय में जो भी निपटने के उपरांत अगर न्यायालय को आदेश देता है, उसकी पालना होगी। अन्यथा सरकार उनके समक्ष विचाराधीन रिपोर्ट की समीक्षा कर न्याय उचित निर्णय लेगी। वह कोर्ट का अंतरिम आदेश है। सरकार उसकी पालना कर रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर टीका-टिप्पणी करना ठीक नहीं है और जब तक न्यायालय पोस्टिंग का भर्ती के संबंध में आदेश का निर्णय का इंतजार करेगी। सरकार न्यायालय समक्ष अपना पक्ष रखा।

वहीं, लोकेश शर्मा के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकेश शर्मा एकदम पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के सबसे नजदीकी अधिकारी थे। हमने जो आरोप लगाया था, उस वक्त हम आप कहते थे आज पुख्ता प्रमाण है कि हमारे जन प्रतिनिधियों के फोन टैप किया जा रहे थे। उस वक्त हमको गलत

बताया गया। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी ने स्वयं स्वीकारा कि हां मैंने ही मुख्यमंत्री के कहने से जनप्रतिनिधियों के फोन टैप किए थे, जिसमें जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे। आज इस बात का पुख्ता प्रमाण हो गया है कि उन्होंने फोन टैपिंग किए और उनके फोन टैपिंग की स्वीकृतियों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामला न्यायलय में विचाराधीन है और मैं तो यह कह सकता हूं कि निंदनीय कार्य किसी की सुरक्षा किसी की निष्पक्षता का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर फोन टैपिंग कर प्रहार करना गलत था। ऐसे कार्य का हमेशा निंदा करते हैं और चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मंत्री पटेल ने कहा, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून से कोई बच नहीं सकता, जिन्होंने गुनाह किया वह सब फसेंगे। इतना इशारा आपको कर सकता हूं। छोटी मछली लोकेश शर्मा फंसे हैं, बड़े मगरमच्छ कितने दिन बाहर घूम लें, वह भी कानून के दायरे में आएंगे। वहीं, उदयपुर मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान से पहले तो उनका व्यक्तिगत विषय है। राजतिलक होना नहीं होना यह उनका व्यक्तिगत विषय है। परंतु लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सरकार का काम है। सरकार ने वहां पुलिस व्यवस्था कर दी है। धारा-144 की कार्रवाई कर दी है। वहां पर भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, कानून को मनाना चाहिए। भाईचारा कायम रखना चाहिए। आप सब भाइयों का मामला सड़कों पर आना ठीक बात नहीं है।

'डमी' परीक्षार्थी के सहारे परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी पाने के मामले में चार गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान पुलिस के विशेष समूह (एसओजी) ने भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर 'डमी' परिक्षार्थी की मदद से परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी पाने के मामले में तीन शारीरिक शिक्षक व एक व्याख्याता को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त महानिदेशक (एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसओजी को हेल्पलाइन पर शिकायत मिली थी कि आरोपियों ने अपनी जगह पर 'डमी' परीक्षार्थी से परीक्षा दिलाई और इनके द्वारा दी गई बीपीएड की डिग्री भी फर्जी हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर एसओजी ने तीनों आरोपियों के दस्तावेजों की जांच की और शिकायत सही पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश कर रिमांड (अभिरक्षा) में ले लिया गया। यह मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती 2022 का है। एसओजी ने जाखड़ों की ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक पद पर तैनात स्वरूपा राम (निवासी गुडामालानी जिला बाड़मेर) , कुडा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक पद पर तैनात भारमल राम और वनानी भीलों की ढाणी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात लादूराम को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2022 की सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 29 जनवरी 2023 को हुई।

उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद

एकलिंगजी मंदिर में दर्शन के बाद विश्वराज सिंह ने सफेद पगड़ी उतार कर पहनी लाल पगड़ी, शोक खत्म

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर। ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित राजपरिवार के बीच चल रहे विवाद ने अब एक नई दिशा ले ली है। इस विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब विश्वराज सिंह मेवाड़ ने बुधवार को प्रसिद्ध एकलिंगजी मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। यह मंदिर, जो मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यहां के दर्शन मेवाड़ राजघराने के लिए परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक माने जाते हैं। दर्शन के बाद, एक विशेष रस्म निभाई गई, जिसे 'शोक भंग' की रस्म कहा जाता है। इसमें विश्वराज सिंह को सफेद पगड़ी की जगह रंगीन पगड़ी पहनाई गई, जो परंपरागत रूप से शोक से उबरने और नए उत्साह के संकेत के रूप में पहनी जाती है। यह पारंपरिक बदलाव न केवल परिवार के भीतर की स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राजघराने की इस जटिल स्थिति में भी परंपरा और आस्था का एक अहम स्थान है।

इससे पहले, विश्वराज सिंह ने समोर बाग में भी एक और रस्म निभाई थी, जिसमें उन्होंने पारंपरिक तरीके से घोड़ी की पूजा की और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए। ये अनुष्ठान राजघराने के गौरव और परंपरा को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि, यह सब एक खूबसूरत धार्मिक और पारंपरिक संदर्भ में हुआ, लेकिन सोमवार की हिंसक झड़प के बाद यह विवाद एक गंभीर मोड़ ले चुका है। इस दरम्यां दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह ने एक-दूसरे को सोमवार की हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। दोनों ने ही जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वे इस विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों से, परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई हिंसक झड़प से हुई, जिसने न केवल परिवार के भीतर की दरार को और बढ़ा दिया, बल्कि पूरे उदयपुर क्षेत्र में खलबली मचा दी। उदयपुर की शांतिपूर्ण छवि अब एक नई दिशा में बदलती दिखाई दे रही है, जहां परंपरा और आस्था के साथ-साथ प्रशासनिक विवाद भी गहराता जा रहा है। अब देखना यह है कि इस झगड़े का समाधान कैसे निकाला जाता है, और क्या राजघराने की आस्था और परंपरा को बचाए रखने में प्रशासन सक्षम हो पाता है या नहीं।

दृष्टिबाधित अध्यापक को परेशान करने का मामला

अधिकारी सहित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर में एक सरकारी स्कूल के दृष्टिबाधित अध्यापक और अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी को परेशान करने की शिकायत के मामले में सम्बद्ध शिक्षा अधिकारी व प्रधानाध्यापकि सहित तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित अध्यापक अजय देवेंदा ने यहां शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद मंत्री ने उक्त आदेश दिए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार दृष्टिबाधित अध्यापक अजय देवेंदा यहां करतारपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। दिलावर ने उन्हें कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय प्रारंभिक-जयपुर ग्रामीण) कृष्ण पाल सिंह, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजू तथा आरोपी अध्यापिका रेखा सोनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश संयुक्त निदेशक शिक्षा मंजू शर्मा को दिए हैं।

पीड़ित ने शिक्षा मंत्री को बताया कि अध्यापिका रेखा सोनी का स्कूल के बच्चों से हाथ पैर दबवाने का वीडियो गत दिनों वायरल हुआ था जिसपर उसके खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की थी। उन्होंने बताया कि अध्यापिका उन्हें वीडियो वायरल करने का दोषी बता कर झूठे आरोप लगाकर लगातार प्रताड़ित कर रही है। उक्त अध्यापिका की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण पाल सिंह ने उनके खिलाफ '16 सीसी' की कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस दिया है। देवेंदा ने बताया कि उनपर विद्यालय में वीडियो बनाकर वायरल करने, अध्यापिका रेखा सोनी की छवि खराब करने तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर विद्यालय में मोबाइल का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने उनकी शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल की प्रधानाध्यापिका अंजू और शिक्षिका रेखा सोनी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही करने के निर्देश संयुक्त निदेशक शिक्षा जयपुर को दिए हैं। पीड़ित अजय देवेंदा पैरालंपिक के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने 17 खातेदारों के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा

जयुपर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप ब्यावर जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत अवैध अतिक्रमण, खनन व परिवहन के विरुद्ध निरंतर सख्ती बरत रहे हैं। इसी के तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग 23 लाख 50 हजार की राशि का बड़ा जुर्माना लगाया गया। खनिज विभाग के एमई जगदीश मेहरावत ने बताया कि गत दिनों शिकायत के आधार पर जांच के दौरान मसूदा तहसील के राजस्व ग्राम कानाखेड़ा के ग्राम कुंडिया में मौके पर पहुंचने पर खनिज क्वार्ट्ज फेल्सपार का ताजा खनन किया जाना पाया गया। इस पर विभाग द्वारा मौके पर जीपीएस फोटो लेकर हल्का पटवारी को मौके पर बुलाया गया। पटवारी की जांच पर उक्त भूमि खसरा संख्या 522 ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा ब्यावर में आती है जो कि खातेदारी है। खनिज विभाग द्वारा जांच करने पर उक्त खसरे में एक खनन पिट मिला जिसमें फेल्सपार खनिज का ताजा खनन करना पाया गया।खनिज विभाग द्वारा जीपीएस एवं फीते की सहायता से खनन का मापन किया गया एवं गणना करने पर लगभग 1958 टन खनिज का अवैध खनन कर बेचान किया जाना पाया गया। इस पर खनिज विभाग द्वारा अमना पुत्री निजाम सहित 17 अन्य खातेदारों के विरुद्ध सदर थाना ब्यावर में एफआईआर दर्ज कराई गई एवं फेल्सपार की रॉयल्टी 120 रुपए प्रति टन तथा इसकी 10 गुना वसूली योग्य राशि लगभग 23 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

दीया कुमारी ने की केंद्र से 900 नए आंगनबाड़ी भवनों की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर आगामी जनवरी में उदयपुर में आयोजित किया जायेगा। इसमें केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री समेत सभी राज्यों के इस विभाग के मंत्री भाग लेंगे तथा आँगनबाड़ी केन्द्रो, पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर राज्यों की आवश्यकतानुसार एक रोडमैप तैयार करेंगे।उपमुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की।

उपमुख्यमंत्री ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से माँग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी किया जाये जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके। उपमुख्यमंत्री ने माँग की है कि पूरक पोषाहार दरों को बढ़ाया जाये। पूरक पोषाहार की दरों का वर्ष 2017 में पुनर्निधारण किया गया था जिसके युक्तियुक्त पुनर्निधारण की आवश्यकता है।

श्रीमती दीया कुमारी ने राज्य में नये 900 आंगनबाड़ी भवनों की माँग करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र को भिजवा दिये गया है जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत के लिए हर पाँच साल में जारी होने वाली 3000 रुपये की राशि को भी जरुरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत की लागत पचास हज़ार से एक लाख तक होनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ रुपये के केन्द्रांश तथा किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने और 340 आँगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की भी मांग की।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ी, एसएमएस में भर्ती

जयपुर। राज्य के कृषि एवं पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उनके परिजन और स्टाफ के सदस्य उन्हें उपचार के लिए एसएमएस हॉस्पिटल लेकर आए। यहां उन्हें डॉक्टरों ने उपचार के लिए मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया है। एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक देर रात डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के पेट में दर्द, उल्टी, जलन और एसिडिटी की शिकायत थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एसएमएस की इमरजेंसी में लाया गया।

राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार ने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन

भरतपुर/दक्षिण भारत। राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार ने अपने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और मंदिर के पुजारी से अंग वस्त्र और भगवान का प्रसाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भरतपुर आए हैं तो बांके बिहारी के दर्शन जरूर करने चाहिए थे। यह यात्रा उस समय की गई जब भाजपा तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी के निधन की सूचना मिली थी। डॉ बाघमार शोक व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रही थीं और मंगलवार रात भरतपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। बुधवार सुबह किला स्थित बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और परिवार के साथ पूजा अर्चना की।

मंदिर महंत मनोज भारद्वाज ने राज्य मंत्री और उनके परिवार को अंग वस्त्र और भगवान का प्रसाद भेंट किया। डॉ बाघमार ने दर्शन के बाद कहा कि मंदिर में आकर एक अलग ही सुकून महसूस हुआ है और ऐसा लगा जैसे सकारात्मक पूजा की हो। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गईं।

बता दें कि बांके बिहारी जी के मंदिर का इतिहास 602 साल पुराना है, जब नागा साधुओं ने यहां विग्रह की स्थापना की थी। 2022 में इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया गया, जिसमें 12 करोड़ रुपए की लागत आई। अब यह मंदिर नए स्वरूप में दर्शनार्थियों के लिए खुला है। इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बांके बिहारी जी ने हमेशा भरतपुरवासियों पर अपनी कृपा बरसाई है और उनके दर्शन से आत्मिक शांति मिलती है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगी परीक्षा

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा-2024 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर के 130 केन्द्रों पर होगा। छः पारियों में (प्रथम पारी प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे एवं द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक) आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 2 लाख 60 हजार 163 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) देवेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिये कलक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका संचालन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 29 नवंबर एवं 30 नवंबर 2024 तक प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं, 01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2024 को को प्रातः 6 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा।

महाकुम्भ को डिजिटल स्वरूप देने के लिए गूगल के साथ किया समझौता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

प्रयागराज/भाषा। महाकुम्भ 2025 को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में यहां परेड मैदान में गूगल ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।

गूगल की ओर से कंपनी के पॉलिसी प्रमुख सिद्धार्थ सिंह और प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इस सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत गूगल 4000 हेक्टेयर में बसने जा रहे महाकुम्भ मेले के लिए 'नेविगेशन' सुविधा उपलब्ध कराएगी। कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी अस्थायी नगर के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने इस समझौते को लेकर कहा, ''प्रधानमंत्री की डिजिटल कुम्भ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ एक एमओयू हुआ है। संगम नगरी का डिजिटल मानचित्र हम देख पाएंगे, हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर हर गतिविधि और आयोजन देख सकेगा।'' महाकुम्भ के आयोजन की नीव कहलाने वाले सफाईकर्मियों, स्वेच्छाग्राहियों और नाविकों को किट और जैकेट वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले कुम्भ में इन सफाईकर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से संदेश दिया था कि वास्तव में स्वच्छ कुम्भ की नीव

वास्तव में ये सफाईकर्मी हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुम्भ भी स्वच्छता, सुरक्षा और भव्यता का प्रतीक बन सकता है। कुम्भ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति सुकून महसूस करके असीम अध्यात्मिक शांति की अनुभूति कर सकता है, यह दृश्य 2019 के कुम्भ में देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने महाकुम्भ के प्रमुख स्नान पर्व गिनाते हुए कहा कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति (शाही स्नान), 29 जनवरी को मौनी अमावस्या (शाही स्नान), 3 फरवरी को बसंत पंचमी (शाही स्नान), 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ेगा। उन्होंने कहा, 26 फरवरी के बाद हम आपका (सफाईकर्मियों) अभिनंदन करने फिर यहां आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रयागराज आगमन है। वह लगभग 6500 करोड़ रुपए से अधिक की कुम्भ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

महाकुम्भ की तैयारी 10 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी : आदित्यनाथ

प्रयागराज/भाषा। महाकुम्भ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करने बुधवार को संगम नगरी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने महाकुम्भ के कार्यों का निरीक्षण किया है और युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कुम्भ के आयोजन (13 जनवरी) से एक महीने पूर्व 10 दिसंबर तक मेले की तैयारी पूरी हो जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ''महाकुम्भ 2025 के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री का यहां 13 दिसंबर को आगमन हो रहा है। वह मां गंगा की पूजा करेंगे, डिजिटल कुम्भ के कार्यों का अवलोकन करेंगे और दिव्य एवं भव्य कुम्भ को लेकर विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे।''

छात्र संघ की जगह युवा संसद के गठन पर विचार करें विवि : योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

प्रयागराज/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे युवाओं के आने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आह्वान दोहराते हुए बुधवार को कहा कि विश्वविद्यालयों को यह विचार करना चाहिए कि छात्र संघ की जगह क्या युवा संसद का गठन कर सकते हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''इस युवा संसद के लिए हर कक्षा में तय होना चाहिए कि पहले ही वर्ष में कोई छात्र चुनाव लड़ने के लिए ना आने पाए। उन्होंने कहा, हर कक्षा में पहले वर्ष प्रतिनिधि चुने जाएं और फिर उन प्रतिनिधियों में तय किया जाए कि कौन दूसरे या तीसरे वर्ष या फिर स्नातकोत्तर कक्षा में चुनाव के मैदान के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और कौन चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, जीवन के अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वे छात्र समाज को दिशा दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक घटना साझा की जिसमें उन्हें एक विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति मिला जिसकी उम्र बहुत अधिक थी। तभी उन्हें किसी ने बताया कि अमुक व्यक्ति छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और उसका बेटा उसी विश्वविद्यालय में बीए का छात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस घटना से मुझे लगा कि उस व्यक्ति ने छात्र संघ का पदाधिकारी बनने के लिए ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। आखिर इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में कोई लंबे समय तक रहना चाहता है तो वह शोध करे। छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी।

झारखंड में 'अबुआ सरकार' की नई पारी आज से शुरू होगी : हेमंत सोरेन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रामगढ़ (झारखंड)/भाषा। झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शपथग्रहण समारोह के बाद बृहस्पतिवार से 'अबुआ सरकार' (हमारी सरकार) की नई पारी शुरू होगी। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ अपने दादा सोबरन सोरेन को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले में अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे।

उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ''मैं अपने दादा सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने हर साल इस स्थान पर आता हूं।'' सोरेन ने अपने गांव वालों को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले अपनी सरकार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। नेमरा के लुकैयाटांड में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के गठन का काम जारी है। सोरेन ने ग्रामीणों से कहा, ''कल से 'अबुआ सरकार' (हमारी सरकार) की नई पारी शुरू होगी। शपथग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को होना है। मैं आप सभी को इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी ने अबुआ सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत की है।'' झामुमो के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार हेमंत के दादा सोबरन की साहूकारों ने उस समय हत्या कर दी थी जब झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन 15 वर्ष के थे।

चिराग ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर खरगे और 'इंडि' गठबंधन की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर संदेह जताने और मतपत्रों से मतदान कराने की वकालत किए जाने को लेकर बुधवार को उनकी आलोचना की।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)अध्यक्ष ने यह भी जानना चाहा कि क्या कांग्रेस और उसके सहयोगियों को उन राज्यों में समस्या है, जहां उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को हराया है । उन्होंने 'इंडि' गठबंधन को चुनौती दी कि अगर उसे पूरा भरोसा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो वह अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करे। हाजीपुर से लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने कहा, ''यह अजीब है कि जब भी विपक्षी दल चुनाव हारते हैं, तो वे ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। वे महाराष्ट्र में ऐसा कर रहे हैं लेकिन झारखंड के बारे में क्या।'' उनकी पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जीत दर्ज की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी)के अध्यक्ष खरगे ने मंगलवार को दिल्ली

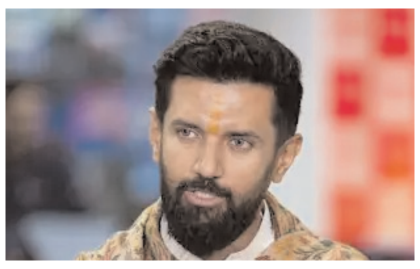

में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाया था। इस संबंध में पूछे गए सवाल का चिराग पासवान जवाब दे रहे थे। पासवान ने कहा, ''चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा किया है। बिहार में, जहां राजग ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 225 सीटों का लक्ष्य रखा है, निश्चिंत रहें, राजद और कांग्रेस यह दावा करेंगे कि वे 235-240 सीटें जीतने जा रहे है और चुनाव के बाद वे अपनी विफलता के लिए ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर वे ईवीएम के बारे में गलतफहमी के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वे बिहार में तब तक विस चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक कि मतदान मतपत्रों के माध्यम से नहीं किया जाता।''

सिक्किम ने हिमनद बाढ़ के खतरों से निपटने के लिए अभियान शुरू किया

गंगटोक/भाषा। सिक्किम सरकार ने ग्लेशियर पिघलने के कारण हिमनद झीलों में पानी बढ़ जाने से बाढ़ के जोखिम को कम करने और जलवायु संतुलन बरकरार रखने के लिए 2024 का अपना चौथा और अंतिम अभियान 27 नवंबर से शुरू कर दिया। ये अभियान पांच दिसंबर तक जारी रहेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हिमनद झीलों के बढ़ते खतरों के मद्देनजर यह मिशन शुरू किया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया कि अकेले सिक्किम में 40 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की पहचान की गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक, पिछले अभियानों में कई उच्च जोखिम वाली झीलों का व्यापक मूल्यांकन किया गया था। इसके अलावा स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से शाको छो और साउथ ल्होनक झील में स्वचालित मौसम एवं जल स्तर निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन निगरानी केंद्रों से रोजाना के मौसम, जल स्तर आदि के आंकड़ों के साथ ही तस्वीरें भी मिलने लगी हैं।

संभल हिंसा: प्रदर्शनकारियों से नुकसान की होगी वसूली, 'पत्थरबाजों' के पोस्टर लगाए जाएंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश सरकार संभल में हाल ही में हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करेगी और 'पत्थरबाजी'करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए जाएंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

संभल पुलिस ने बुधवार को हिंसा में शामिल कई लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में नौ लोगों की पहचान की गई है और लोगों से उन लोगों की पहचान करने में मदद मांगी गई है जिनके चेहरे ढके हुए हैं। संभल शहर के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित जामा मस्जिद के पिछले रविवार को हो रहे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान हुए पथराव में सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। यह सर्वेक्षण एक याचिका पर कराया गया है जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद से पहले उक्त स्थान पर हरिहर मंदिर था। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया, ''प्रदेश सरकार संभल में हुई हिंसा में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। पत्थरबाजों व उपद्रवियों के पोस्टर जगह-जगह लगाए जाएंगे और उनसे नुकसान की वसूली की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जा सकता है।''

बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर डेरी संचालक पर भीड़ ने किया हमला

बरेली/भाषा। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के मीरगंज कस्बे में छेड़छाड़ के एक मामले में हस्तक्षेप करने पर उग्र भीड़ ने डेरी संचालक और उसके भाई पर हमला कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब नौ बजे हुई। जाम गांव के निवासी मनोज और प्रमोद अपनी डेरी बंद करके घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि रईस कुरैशी नामक व्यक्ति सिरौली चौराहे पर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा है। उसे रोकने पर उसने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि कुरैशी ने अपने साथियों अयान, कय्यूम, समीर और करीब 40 अन्य लोगों को बुला लिया। भीड़ ने मनोज और प्रमोद पर लाठियों से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया।

हिंदू नेता की रिहाई तक बांग्लादेशियों को वीजा जारी न किया जाए : अधिकारी

कोलकाता/भाषा। भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि जब तक बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को रिहा नहीं कर देती तब तक के लिए भारतीय अधिकारियों को बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए।

दास की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर बांग्लादेश उप-उच्चायोग को एक ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में यह भी मांग की कि जब तक पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने के लिए कदम नहीं उठाए जाते तब तक दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात को

अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा, आप जानते हैं कि वहां (बांग्लादेश) हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार किया जाता है। इस तरह के अत्याचार को जारी नहीं रहने दिया जा सकता। प्रभु चिन्मय कृष्ण दास ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम उनकी तत्काल रिहाई चाहते हैं।

विदेशी पर्यटक ने ताजमहल में प्रवेश के लिए अलग कतार की मांग की, वीडियो वायरल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

आगरा(उप्र)/भाषा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें एक विदेशी पर्यटक ताजमहल में दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के प्रवेश के लिए अलग कतार की व्यवस्था करने की मांग करता सुनाई दे रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल की 17वीं शताब्दी में बने मकबरे के शाही द्वार पर फिल्माए गए एक मिनट के वीडियो में पर्यटक ने दावा किया है कि वह अपने बुजुर्ग पिता के साथ ताजमहल देखने आया एक 'इंफ्लुएंसर' है।

वीडियो में पर्यटक कहता सुनाई दे रहा है कि अभी तक 70 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका

हूं। भारत और ताजमहल आकर बेहद खुश हूं। में एक 'इंफ्लुएंसर हूं और पूरे विश्व में घूमता हूं। यहां पर सब कुछ बहुत बढ़िया और अच्छा है, लेकिन एक चीज में सुधार के लिए भारत सरकार से गुजारिश करूंगा। वह कहता सुनाई दे रहा कि यहां की सुरक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिये क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटक होने के नाते मैं चाहूंगा कि यहां पर विदेशी पर्यटकों के लिए एक अलग से कतार हो जिससे उन्हें परिसर में प्रवेश करने में परेशानी न हो। स्मारक का प्रबंधन करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद् राज कुमार पटेल ने इस संबंध पर पूछने पर बताया, ''विदेशी पर्यटकों के लिए कोई अलग कतार नहीं बनाई जा सकती। हमारे पास एक सामान्य प्रवेश प्रणाली है। प्रवेश में देरी मुख्य रूप से पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण होती है।''

नगालैंड के मुख्यमंत्री ने कई आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोहिमा/भाषा। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बुधवार को राज्य के पर्यटन, परिवहन, कृषि और उद्यमशीलता क्षेत्रों में सुधार के लिए कई आर्थिक सशक्तीकरण योजनाओं की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने उरा कैब्स नाम के एक घरेलू टैक्सी मंच की भी शुरुआत की जिसे पर्यटकों के लिए सहज यात्रा अनुभव और स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों के लिए स्थिर आय के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। रियो ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आर्थिक

सशक्तीकरण पहलों की शुरुआत की। उराकैब, नगालैंड टूरिज्म कनेक्ट (हॉर्नबिल संस्करण) और डिजिटल सूअर बीमा की शुरुआत करते हुए खुशी हो रही है। ये पहल स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा, राहुल को बदलें, ईवीएम को नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की वजह से नहीं बल्कि इसके नेतृत्व के खराब प्रबंधन की वजह से करारी हार मिली और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा कि वह वोटिंग मशीन की जगह राहुल गांधी को 'बदलने' पर विचार करें।

ईवीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष की हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए भाजपा के लोकसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि

खरगे यदि इवीएम, निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, न्यायपालिका और मोदी सरकार नहीं चाहते हैं तो राहुल गांधी को लेकर 'मंगल ग्रह' पर जा सकते हैं और वहां 'खुशी से' रह सकते हैं।

सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिक्रिया खरगे द्वारा चुनावों में मतपत्र के उपयोग की वापसी की मांग करने के एक दिन बाद आई है।

खरगे ने इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक ठोस अभियान का आह्वान भी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में 'संविधान रक्षक अभियान' को संबोधित करते हुए कहा था, ''उन्हें ईवीएम अपने पास रखने दीजिए। हम ईवीएम नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर से मतदान चाहते हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है और वे कहां खड़े हैं।''

पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार पर अपनी हताशा निकाल रहे हैं। उन्होंने यहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, समस्या मशीन (ईवीएम) में नहीं है। समस्या नेतृत्व (कांग्रेस) के साथ है। ईवीएम ठीक है, राहुल खराब हैं। राहुल को बदलें, ईवीएम को नहीं।

पात्रा ने कहा, आप आरबीएम के कारण चुनाव हार गए हैं, जिसका मतलब है कि राहुल का 'बेकर प्रबंधन'।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि खरगे ईवीएम, निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और न्यायपालिका नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, आप भारत की मौजूदा सरकार भी नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि यह एक अच्छी सरकार नहीं है। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। तब मुझे लगता है कि मंगल ग्रह आपके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। कोई नहीं है वहां... आप वहां जाइए, शहजादा को कुर्सी पर बैठाइए और खुशी से जियें।

प्रतिबंध चौंकाने वाला नहीं, अगर भाजपा में शामिल होता हूं तो यह हटा दिया जाएगा: बजरंग पूनिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। डोप जांच के लिए नमूना देने से इनकार करने के कारण चार साल के लिए निलंबित ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने बुधवार को कहा कि यह सरकार का प्रतिशोधात्मक कदम है और वह भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो यह प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।

नाडा ने कहा कि बजरंग ने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के लिए चयन ट्रायल के दौरान नमूना देने से इनकार करके नियमों का उल्लंघन किया।

डोपिंग रोधी संस्था ने सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान को 23 अप्रैल को इस उल्लघंन के लिए निलंबित किया था। जिसके बाद खेल की विश्व संचालन संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी उन्हें निलंबित कर दिया था।

बजरंग ने पत्रकारों से कहा, ''यह चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि ट्रायल का यह मामला पिछले एक साल से चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने नाडा को नमूना देने से इनकार नहीं किया है। जब वे डोप जांच के लिए मेरे घर आए थे तो वे एक 'एक्सपायरी किट' (दिसंबर 2023 में) लेकर आए थे। मैंने इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। ''

पूनिया और उनकी साथी पहलवान ओलंपियन विनेश फोगाट इस साल के शुरु में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे।

बजरंग ने अपने बचाव में कहा, ''आप किसी भी खिलाड़ी को 'एक्सपायरी किट' नहीं दे सकते। जहां तक मेरा सवाल है तो मेरी टीम वहां थी इसलिए उन्होंने यह देख लिया। वे 2020, 2021, 2022 की 'एक्सपायरी किट' लेकर आए थे। '' उन्होंने कहा, ''मैंने मूत्र का नमूना दिया था लेकिन फिर मेरी टीम ने किट की जांच की और पाया कि यह 'एक्सपायर' (तारीख खत्म होना) हो चुकी थी। इसलिए हमने किट का वीडियो बनाया और हमने नाडा को मेल किया। लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की।''

सुविचार

समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है..!

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अब तो चुप्पी तोड़ें यूनुस!

बांग्लादेश से आ रहीं खबरों पर गौर करें तो ऐसा आभास होता है कि यह पड़ोसी देश एक बार फिर 'वर्ष 1971' से गुजरने को आमादा है। इसकी अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस उन ग़लतियों को दोहरा रहे हैं, जो कभी जुल्फिकार अली भुट्टो, याह्या खान, टिक्का खान और एएके नियाजी ने की थीं। बस फर्क इतना है कि तब शिकस्त और बंटवारे का ठीकरा फोड़े जाने के लिए कई सिर थे, अब यूनुस अकेले हैं। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वहां आम लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तब भारत उनके लिए संकटमोचक बनकर आया था। हमारी हर सरकार ने बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए सहयोग किया, लेकिन इसका बदला जिस तरह मिला, वह दु:खद है। हाल के महीनों में वहां जिस भयानक स्तर पर हालात बिगड़े, उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इस पड़ोसी देश में भारतविरोधी भावनाओं की जड़ें काफी गहरी हैं। बांग्लादेश में 'अर्थशास्त्री' के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उनके घरों, प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बांग्लादेश में कोई सरकार है। अगर सरकार है तो कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या यूनुस ने उनके साथ कोई गुप्त संधि कर रखी है या वे जानबूझकर धृतराष्ट्र बन रहे हैं? अत्याचार की कई घटनाओं के बाद हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया, वह बांग्लादेश में गहरे असंतोष के बीज बो सकता है। इससे उसकी अखंडता और संप्रभुता भी खतरे में पड़ सकती हैं।

चिन्मय कृष्णदास पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी झंडे का अपमान किया, चूंकि भगवा ध्वज को ज्यादा ऊंचा फहराया गया था! इस आरोप का यह कहते हुए खंडन किया जा रहा है कि 'बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने' जैसी कोई मंशा ही नहीं थी। अगर बांग्लादेशी सरकार उक्त आरोप को इतना गंभीर मानती है तो उसे उन लोगों को भी जेल में डालना चाहिए, जो कुछ महीने पहले शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चला रहे थे। क्या यूनुस इतना हौसला दिखा पाएंगे? अगर भगवा झंडा फहराना 'देशद्रोह' है तो राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर हथौड़े चलाना, महिला प्रधानमंत्री के वस्त्रों का सड़कों पर अश्लील प्रदर्शन करना कौनसी 'देशभक्ति' है? जिन लोगों ने पूरे बांग्लादेश में हिंसक हुड़दंग मचाया, अल्पसंख्यकों पर हमले किए, वे तो आज तक खुले घूम रहे हैं। यूनुस इतनी फुर्ती ऐसे तत्त्वों को गिरफ्तार करने में क्यों नहीं दिखाते? वहां तो वे पूरी तरह उदासीन और निष्क्रिय दिखाई देते हैं। वास्तव में बांग्लादेश में जिसकी भी सरकार रही हो, इसने हमेशा 'दो चेहरे' रखे। एक ऐसा, जिसे दिखाकर यह खुद को विकासशील, प्रगतिशील और कर्मठ बताता रहा। इससे इसे विभिन्न देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहायता लेने में आसानी हुई। इसका दूसरा चेहरा वह था, जो लगभग अदृश्य ही रहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कई घटनाएं हुईं, लेकिन उनके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं हुई। वहां कई लेखकों को अपने प्रगतिशील विचारों की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। कई तो वहां से जान बचाकर भागे, क्योंकि कट्टरपंथी किसी भी वक्त धावा बोल सकते थे। बांग्लादेशी नेतागण वोटबैंक और कुर्सी बचाने के लिए कट्टरपंथी तत्त्वों से समझौते करते रहे। वहीं, आए दिन अत्याचारों से त्रस्त होकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए। यह सिलसिला आज तक जारी है। बांग्लादेश में विदेशी मीडिया के कैमरे नहीं पहुंचे, जो पहुंचे, वे भी 'धुंधले' हो गए! दुर्भाग्य रहा कि भारत समेत कई देशों के बड़े-बड़े नेता हिंदुओं के मानवाधिकारों के लिए खुलकर बोलने से हिचकते रहे। अब जबकि बांग्लादेशी हिंदू अपने लिए ख़ुद आवाज उठा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता चुप्पी तोड़ने लगे हैं। चुप्पी तो यूनुस को भी तोड़नी चाहिए। अगर वे बांग्लादेश में शांति स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें मदद मांगनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनकी चुप्पी रह जाए और बांग्लादेश टूट जाए!

ट्वीटर टॉक

लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सेवा के साथ ही सदन संचालन में उच्च आदर्श स्थापित करने वाले मावलंकर जी ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का कार्य किया।

–ओम बिरला

दिल्ली में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन और अन्त्योदय की भावना से प्रेरित जनकल्याण का संकल्प, सदैव नयी उर्जा प्रदान करता है।

–दीया कुमारी

महान समाज-सुधारक एवं राष्ट्र-सेविका समिति की संस्थापिका, लक्ष्मीबाई केलकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों ने नारी शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की दिशा में नई क्रांति का सूत्रपात किया।

–भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

पटेल का ऋषिकर्म

अंग्रेज किसानों पर जुल्म और अत्याचार कर रहे थे। सरदार पटेल ने महसूस किया कि किसानों को शिक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। उन्हीं दिनों पटेल ने किसानों के घर-घर का दौरा किया। उन्हें समझ आया कि जब तक किसानों के परिवारों को थोड़ी-बहुत शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक उन्हें सरलता से समझा पाना मुश्किल है। पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें शिक्षा की अहमियत बताई। एक दिन पटेल ने किसान के घर में खेल रही बालिका को बुलाया और उसे एक पुस्तक दिखाते हुए बोले, 'बेटा जानती हो, यह किताब है। इसको पढ़ने से बच्चा समझदार हो जाता है।' बात सुनकर बालिका तोतली भाषा में बोली, 'पर किताब पढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए। जैसे मां हर बात समझाती है, वैसे ही किताब कोई समझाएगा तो मैं भी पढ़ूंगी।' बालिका की चतुराई भरी बातें सुनकर पटेल दंग रह गए। उन्होंने ठान लिया कि गुजरात में एक विद्यापीठ की स्थापना करनी होगी, जिससे बच्चों को कुछ पढ़ने-लिखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया।

सामयिक

जहां दुनिया के विकसित देशों में अधिकांश आबादी इंटरनेट से जुड़ने के कारण प्रगति की राह में सरपट दौड़ रही है, तो गरीब मुल्कों में यह प्रतिशत विकसित देशों के मुकाबले करीब एक चौथाई ही है। ऐसे में समतामूलक आदर्श समाज की स्थापना के लिये डिजिटल डिवाइड को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके मद्देनजर हमारी कोशिश हो कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप समावेशी हो। ताकि आधुनिक तकनीक तक बच्चों की समान व सुरक्षित पहुंच हो सके। निर्विवाद रूप से बच्चे आने वाले कल के लिये देश का भविष्य निर्धारक होते हैं।

जलवायु परिवर्तन के खतरों से बच्चों को बचाएं

ललित गर्ग
मोबाइल : 9811051133

हाल ही में प्रस्तुत हुई यूनिसेफ की रिपोर्ट 'द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन इन चेंजिंग वर्ल्ड' ने भारत में बच्चों के भविष्य को लेकर उत्पन्न चुनौतियों, त्रासद स्थितियों एवं भयावह भविष्य को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि साल 2050 तक भारत में 35 करोड़ बच्चे जनसांख्यिकीय बदलावों, जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी बदलावों की चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। उस समय जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के बाद जीवन में जलवायु परिवर्तन के संकटों से जुझना होगा, भीषण लू, गरमी, बाढ़, तूफान, चक्रावात और अनेक जलवायु जनित बीमारियों से सामना करना होगा। वायु प्रदूषण की विभीषिका, गहराते जल संकट, सिमटते प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन व रोजगार की विसंगतियों के बीच आने वाली पीढ़ी के बच्चों का जीवन निस्संदेह संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण एवं संकटपूर्ण होगा। वर्ष 2021 में बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कुल 163 देशों की सूची में 26वें स्थान पर था। ऐसे में भारत में बच्चों को अधिक गर्मी, बाढ़ और वायु प्रदूषण से गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। खासकर ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों में यह संख्या ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 2050 में बच्चों को 2000 के दशक की तुलना में लगभग आठ गुना ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। जाहिर है, जलवायु संकट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा तथा पानी जैसे आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। चिंता की बात यह है कि इन तमाम विसंगतियों, विषमताओं व नेतृत्व की अदूरदर्शिता के बीच बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहे खतरों के लिये संवेदनशीलता के साथ सावधान एवं सतर्क होने एवं उचित-प्रभावी कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।

इसी तरह, गहरे डिजिटल विभाजन के बीच एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बच्चों के लिए अच्छी और बुरी, दोनों हो सकती है। एक ताजा आंकड़ा बताता है कि उच्च आय वाले देशों में 95 फीसदी आबादी इंटरनेट से जुड़ी है, तो निम्न आय वाले देशों में सिर्फ 26 प्रतिशत लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। भारत में वर्तमान में इंटरनेट की व्यापकता ने बच्चों के जीवन में अनेक संकट खड़े किये हैं। यूनिसेफ ने इस डिजिटल डिवाइड को पाटने और बच्चों तक नयी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षित एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी पहल की वकालत की है। बच्चे चूंकि हमारा भविष्य हैं, इसलिए बच्चों और उनके अधिकारों को सरकारी नीतियों-रणनीतियों के केंद्र में रखना समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के निर्माण एवं संतुलित-आदर्श समाज-व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अक्सर यह सवाल विमर्श में होता है कि धरती के प्रति गैर-जिम्मेदार व्यवहार के चलते हम कैसा देश आने वाली पीढ़ियों के लिये छोड़कर जाएंगे। आने वाले पच्चीस वर्षों में बच्चों पर लू का 8 गुणा, बाढ़ का 3 गुणा एवं जंगली आग का दोगुणा खतरा होगा। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने बच्चों के भविष्य की तस्वीर उकेरते हुए विभिन्न चुनौतियों के मुकाबले के अनुरूप नीति निर्माण की जरूरत बतायी है। यूनिसेफ ने सदी के पांचवें दशक तक की तीन महत्वपूर्ण वैश्विक प्रवृत्तियों का खाका खींचा है। ये घटक नौनिहालों के भविष्य के जीवन को नया स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

वर्ष 2050 तक देश की आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। दरअसल, मौजूदा दौर में जिस तेजी से गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, जाहिर है ऐसी स्थिति में पहले से आबादी के बोझ तले दबी नागरिक सेवाएं चरमरा जाएंगी। ऐसे में सत्ताधीशों के लिये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के संकट के बीच बच्चों के अनुरूप शहरी नियोजन को अपनी प्राथमिकता बनाएं और बच्चों के अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से जुझारु, सुरक्षित एवं निरापद शहरी नियोजन के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और टिकाऊ शहरी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी जाये। शहर बेहतर जीवन के लिए बेहतरीन अवसर और उम्मीद दे सकते हैं। वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पन्न करते हैं और उन्हें तेजी से विकास हासिल करने के लिए इंजन माना जाता है। वे विकास और नवाचार, विविधता और कनेक्टिविटी के दुनिया के सबसे मजबूत स्रोतों में से हैं और संभावित रूप से बच्चों को जीने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं।

बढ़ता शहरीकरण बड़ी असमानताओं को भी जन्म दे सकते हैं। आज शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 4 बिलियन लोगों में से लगभग एक तिहाई बच्चे हैं। यह अनुमान है कि 2050 तक, दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्रों में रहेंगे, जिनमें से कई झुग्गी-झोपड़ियों में रहेंगे। इसलिए शहर स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान कर सकते हैं, भीड़भाड़ और उच्च प्रवेश लागत के कारण सबसे गरीब शहरी बच्चे उन तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। अन्य चुनौतियाँ जो शहरी गरीबों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को, उनमें भीड़भाड़ और अपर्याप्त सफाई व्यवस्थाएं शामिल हैं-जो बीमारियों के फैलने में सहायक होती हैं-किफायती और सुरक्षित आवास की कमी, परिवहन की खराब पहुंच और बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि आदि हैं। उल्लेखनीय है कि उस समय देश जनसांख्यिकी बदलावों की चुनौती से जूझ रहा होगा। आकलन किया जा रहा है कि इस बदलाव के चलते ही वर्तमान की तुलना में बच्चों की संख्या में करीब दस करोड़ की कमी आएगी। वर्तमान में पूरी दुनिया में एक अरब बच्चे उच्च जोखिम वाले जलवायु खतरों का मुकाबला कर रहे हैं, तो अगर सरकारें अभी से नहीं चेती तो 2050 की स्थिति का सहज आकलन किया जा सकता है। मासूम चेहरों एवं चमकती आंखों का नया बचपन भारत के भाल पर उजागर एवं कायम करने के लिये सरकारों को गंभीर होना होगा।

बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान आधुनिक मानवतावाद और पूंजीवाद से प्रभावित होकर प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इससे परिवारों और बाल देखभाल प्रदाताओं पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। वर्तमान में मौजूद रहने के बजाय, लोग भविष्य के बारे में सोचने में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। और ज्यादातर मामलों में वे इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि व्यापक अर्थों में सफल जीवन कैसा हो सकता है, बल्कि इसके बजाय वे स्कूल और कार्यस्थल में सफलता के बारे में सोच रहे हैं। यह कुछ कौशलों पर बहुत अधिक जोर देता है, जबकि अन्य-जैसे रचनात्मकता, सामाजिक क्षमता, जीवनमूल्य और उत्साह-को कम महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे अधिक उन्नत शैक्षणिक ट्रैक या अधिक प्रतिष्ठित करियर में चयन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों में कई प्रतिभाएँ अविकसित रह जाती हैं। अगर समाज को भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है-चाहे वह भविष्य आखिरकार कैसा भी क्यों न हो, तो भविष्य के खतरों की आहट को सुनते हुए जागरूक होना होगा। साफ है, नीति के स्तर पर प्रदूषण एवं बदलते मौसम की मार के लिये काम करना होगा। कम से कम भविष्य या बच्चों के लिये तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। निश्चित ही यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट बच्चों के भविष्य की चिंताओं पर मंथन करने तथा उसके अनुरूप नीति-नियंताओं से नीतियां बनाने का सबल आग्रह करती है। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में डिजिटल विभाजन भी एक बड़ी चुनौती होगी। तब तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग चरम पर होगा। जाहिर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जहां तरक्की का मुख्य साधन होगी, वहीं इसकी विसंगतियों का प्रभाव रोजगार के अवसरों एवं सामाजिक-पारिवारिक संरचना पर भी पड़ेगा।

जहां दुनिया के विकसित देशों में अधिकांश आबादी इंटरनेट से जुड़ने के कारण प्रगति की राह में सरपट दौड़ रही है, तो गरीब मुल्कों में यह प्रतिशत विकसित देशों के मुकाबले करीब एक चौथाई ही है। ऐसे में समतामूलक आदर्श समाज की स्थापना के लिये डिजिटल डिवाइड को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके मद्देनजर हमारी कोशिश हो कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप समावेशी हो। ताकि आधुनिक तकनीक तक बच्चों की समान व सुरक्षित पहुंच हो सके। निर्विवाद रूप से बच्चे आने वाले कल के लिये देश का भविष्य निर्धारक होते हैं। ऐसे में हर लोक कल्याणकारी सरकार का नैतिक दायित्व है कि अपनी रीतियों-नीतियों में बच्चों के हितों व अधिकारों को प्राथमिकता दे। तभी हम उनके सुखद भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।

नजरिया

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मारकाट कब थमेगी?

डॉ. सत्यवान सौरभ
मोबाइल : 9466526148

संभल में दायर याचिका वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह के लिए दायर याचिकाओं की तरह ही है। मुख्य मुद्दा यह है कि कानून-'पूजा स्थल अधिनियम, 1991' को कैसे समझा जाता है। संभल की ज़िला अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश एक याचिका के आधार पर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर स्थल पर बनी है। इस आदेश के कारण स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे अपने धार्मिक अधिकारों और विरासत पर हमला माना। जब सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। रिपोर्ट बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों दोनों को चोटें आईं और मौतें हुईं। भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है।

संभल के सिविल जज की अदालत में विष्णु शंकर जैन की ओर से जामा मस्जिद को लेकर वाद दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि समेत 8 वादी हैं। वादियों ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जामा मस्जिद समिति को विवाद में पार्टी बनाया है। याचिका में कहा गया-'मस्जिद मूल रूप से एक हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में बदल दिया गया। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहाँ कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था।' मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, वह अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के समय भी इस पर ज़ोर दिया था। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक़ जताता है और हिंदू पक्ष के दावे, किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही को कानून की अवहेलना बताया है। याचिकाकर्ताओं के दावे के बारे में कानून क्या कहता है? याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद स्थल पर अपना दावा स्थापित करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी मुकदमों में, प्रारंभिक दावों को आम तौर पर अंकित मूल्य (प्रथम दृष्टया) पर स्वीकार कर लिया जाता है, अगर मुकदमा विचारणीय माना जाता है तो बाद में और सबूत पेश किए जा सकते हैं। हालाँकि, कोई भी दावा जो पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की कोशिश करता है, उसे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को मौजूद थे। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या कहता है? अधिनियम पूजा स्थलों के किसी भी रूपांतरण पर रोक लगाता है और यह अनिवार्य करता है कि उनका धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। विशेष रूप से, धारा 3 किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य संप्रदाय या संप्रदाय के पूजा स्थल में रूपांतरण पर रोक लगाती है। धारा 4 में कहा गया है कि उस तिथि को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन के सम्बंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त (समाप्त) कर दी जाती है, जिससे ऐसे रूपांतरणों के सम्बंध में नए मुकदमे दायर नहीं किए जा सकते। उल्लेखनीय रूप से, यह अधिनियम अपने अधिनियमन के समय पहले से ही विचाराधीन विवादों पर लागू नहीं होता है, जैसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला, जिसने समकालीन विवादों में इसके आवेदन को जटिल बना दिया है।

संभल के मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने से पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या दीवानी मुकदमा विचारणीय है। इस एकपक्षीय निर्णय (दोनों पक्षों को सुने बिना) ने इसकी वैधता और निष्पक्षता के बारे में और विवाद पैदा कर दिए हैं। न्यायालयों को 1991 के अधिनियम की मंशा को बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि 15 अगस्त, 1947 तक के स्थलों के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले विवादों को खारिज कर दिया जाए, अनावश्यक सर्वेक्षण या कार्यवाही से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं।

न्यायालयों ने इन टाइटल मुकदमों को कैसे अनुमति दी है? पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, अदालतों ने ज्ञानवापी और मथुरा जैसे स्थानों से सम्बंधित टाइटल मुकदमों को बनाए रखने योग्य क़रार देकर अनुमति दी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी ने संकेत दिया कि अधिनियम के तहत किसी स्थान की धार्मिक प्रकृति को बदलना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके ऐतिहासिक चरित्र की जांच अभी भी अनुमेय हो सकती है। इस व्याख्या ने ज़िला न्यायालयों को अधिनियम की मंशा का सीधे उल्लंघन किए बिना ऐसी याचिकाओं पर विचार करने का आधार प्रदान किया है।

संभल के मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने से पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या दीवानी मुकदमा विचारणीय है। इस एकपक्षीय निर्णय (दोनों पक्षों को सुने बिना) ने इसकी वैधता और निष्पक्षता के बारे में और विवाद पैदा कर दिए हैं। न्यायालयों को 1991 के अधिनियम की मंशा को बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि 15 अगस्त, 1947 तक के स्थलों के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले विवादों को खारिज कर दिया जाए, अनावश्यक सर्वेक्षण या कार्यवाही से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को ऐतिहासिक शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने, हिंसक झड़पों के जोखिम को कम करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

प्रार्थना

चटगाँव में बुधवार को न्यायालय भवन में अधिवक्ता स्वर्गीय सैफुल इस्लाम अलिफ़ की अंतिम संस्कार प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वकीलों के अनुसार, इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ़्तारी को लेकर बांग्लादेश के बंदरगाह शहर चटगाँव में हुई झड़पों के दौरान मंगलवार को वकील की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।

मोहम्मद रफी के बेटे ने अपने पिता के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा की

पणजी/भाषा। मशहूर गायक मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने अपने पिता के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा की है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अगले महीने की जाएगी। आगामी 24 दिसंबर को रफी की जन्म शताब्दी होगी। भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में मंगलवार को हिंदी फिल्म जगत के सबसे प्रसिद्ध गायकों में शामिल रहे रफी साहब को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में और कुछ विदेशी भाषाओं में 1,000 से अधिक फिल्मों में गीत गाए हैं।

शाहिद ने कहा कि वह अपने पिता के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्देशक उमेश शुक्ला के साथ बातचीत कर रहे हैं।

संभल हिंसा पूर्व नियोजित थी, दूसरा सर्वे 'एडवोकेट कमिश्नर' के आदेश पर हुआ था : हिंदू पक्ष के वकील

संभल/भाषा

संभल की शाही जामा मस्जिद में गत रविवार को हुआ सर्वे अदालत के आदेश पर नहीं होने के मस्जिद प्रबंध समिति के आरोपों के बाद बुधवार को हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि दूसरा सर्वेक्षण 'एडवोकेट कमिश्नर' के आदेश पर हुआ था और यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था।

हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, ''दोबारा सर्वे कोई जल्दबाजी का निर्णय नहीं था। इस सर्वे का आदेश एडवोकेट कमिश्नर का था।'' उन्होंने कहा, ''जिस दिन बवाल हुआ, तब मैं वहां मौजूद था। मुझे लगता है यह (हिंसा) पूर्व नियोजित था। उस समय उक्त मस्जिद में दूसरे पक्ष (मुस्लिम पक्ष) की ओर से तीन अधिवक्ता, मस्जिद कमेटी के लोग और इमाम भी मौजूद थे और उन्होंने भी शांति की अपील की थी।'' शर्मा ने कहा, ''उन्होंने (उपद्रवियों) हमारी तरफ भी पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ा लेकिन वे पुलिस पर लगातार ईंट-पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस पर गोलीबारी उन्होंने ही की। कई पुलिसकर्मियों को छर्रे लगे। उपद्रवियों ने अपना चेहरा ढका हुआ था।'' उन्होंने कहा, ''अब 29 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे।''

प्रशासन द्वारा जबरन वजूखाने का पानी खाली कराने के आरोप पर शर्मा ने कहा, ''हौज तो हर हफ्ते खाली किया जाता है। यदि हौज खाली नहीं होता तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कैसे होती?'' उन्होंने कहा, ''तथाकथित (जामा) मस्जिद में वर्ष 1978 तक हिन्दू पक्ष भी पूजा करने जाता था। वर्ष 1978 में दंगे के बाद हिन्दू पक्ष का जाना बंद हो गया था।'' शर्मा ने कहा, ''यहां एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) का बोर्ड भी लगा है। यह एएसआई द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। यहां हर साल एएसआई दो बार सर्वे भी करता है। जब यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो यहां नमाज होना भी उचित नहीं है।''

समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें 'एडवोकेट कमिश्नर' से कोई आपत्ति नहीं है, यह अदालत का अधिकार है। उनके बेटे सोहेल महमूद का नाम भी हिंसा के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में है। इकबाल महमूद ने कहा,''हमारी यह सोच है, कोई भी अदालत हो बिना दूसरे पक्ष को सुने कैसे आदेश दिया गया। दूसरे पक्ष को बुलाया ही नही गया,चार घंटे में फैसला सुना दिया गया। कमीशन होगा कमीशन आ भी गया , रिपोर्ट भी तैयार हो गया हमें जवाब देने और सफाई देने का मौका नहीं मिला कानूनन मिलना चाहिए।'' भीड़ के भड़कने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी थी, जब पुलिस जामा मस्जिद के पास जमा हुई तो लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई। उन्होंने कहा, ''जब लोग जमा हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसी ने पीछे से ईंट फेंकी और फिर पुलिस ने गोलियां चलाईं। जब मस्जिद के वजूखाने से पानी निकला तो लोगों को लगा कि खुदाई हो रही है।''

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति 'खतरनाक' : हसन महमूद

कोलकाता/भाषा। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि भारत विरोधी बयानबाजी और कट्टरपंथियों एवं आतंकवादी ताकतों को बढ़ावा देना ''परस्पर संबंधित'' रणनीतियां हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को ''पूर्ण अराजकता'' की ओर धकेल दिया है। उन्होंने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लेदश की अंतरिम सरकार पर लोकतंत्र को ''भीड़तंत्र'' में तब्दील करने का आरोप लगाया।

बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद बिगड़े हालात के बाद अपना देश छोड़कर आए महमूद ने हाल ही में एक अज्ञात स्थान से टेलीफोन पर एक विशेष साक्षात्कार में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को ''खतरनाक'' करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी सहित चरमपंथी समूह सक्रिय हो गए हैं। महमूद ने जोर देकर कहा कि हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हमलों का घटनाक्रम एक ''चिंताजनक'' स्थिति को दर्शाता है। ''अल्पसंख्यक विरोधी भावना को दर्शाता है जो चरमपंथी बयानबाजी से मेल खाती है, जिससे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ रहे हैं।'' इस बीच, बांग्लादेश के चटगांव शहर में एक वकील की हत्या और एक प्रमुख हिंदू नेता की गिरफ्तारी को लेकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के आरोप में कम से कम 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

नेपाली कांग्रेस के नेता ने चीन से बीआरआई ऋण को लेकर चेताया

काठमांडू/भाषा। नेपाली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को कहा कि नेपाल बीआरआई व्यवस्था के तहत चीन से अनुदान और तकनीकी सहायता स्वीकार कर सकता है, लेकिन ऋण नहीं। नेपाली कांग्रेस (एनसी) नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री के पी ओली की दो दिसंबर से शुरू होने वाली चीन यात्रा से कुछ दिन पहले आई है। नेपाली कांग्रेस नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के अध्यक्ष ओली के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है।

'नेपाल के लिए बीआरआई के रणनीतिक निहितार्थ' विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये महत ने कहा कि नेपाल बीआरआई व्यवस्था के तहत चीन से अनुदान और तकनीकी सहायता स्वीकार कर सकता है, लेकिन ऋण नहीं। उन्होंने कहा, ''हम पहले से ही अतीत में लिए गए विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों के बोझ तले दबे हुए हैं, इसलिए हम विकास सहायता के नाम पर नया ऋण नहीं ले सकते।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि नेपाल सड़कों और संपर्क के लिए बीआरआई के तहत चीन से सहायता मांग सकता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता अनुदान या तकनीकी सहायता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''हमें किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने राष्ट्रीय हित पर विचार करने के साथ-साथ अपनी आवश्यकता का आकलन करने की भी जरूरत है।'' नेपाल और चीन ने मई 2017 में बीआरआई के की पहली रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके तहत एक भी परियोजना कार्यान्वित नहीं हुई है।

भारत-चीन संबंध सुधरने के बाद, विजय सेतुपति की 'महाराजा' बनी पहली रिलीज फिल्म

मुंबई/एजेन्सी

विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप अभिनीत महाराजा इस शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024 को चीन में रिलीज़ होने वाली है। तमिल सस्पेंस फ़िल्म पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए पिछले महीने हुए समझौते के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने के बाद चीनी दर्शकों के लिए प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय सिनेमा बन जाएगी। महाराजा की प्री-स्क्रीनिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और यहाँ इसकी रिलीज़ दो प्रमुख प्रतिस्पर्धियों - हॉलीवुड की ग्लेडिएटर खख और स्थानीय फ़िल्म हर स्टोरी के साथ मेल खाती है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि फिल्म को चीनी मूवी रिव्यू साइट डोबन पर 8.7/10 की उच्च रेटिंग मिली है और इसे हाल के वर्षों में सबसे अधिक रेटिंग वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। निथिलन स्वामीनाथन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ममता मोहनदास और नट्टी नटराज भी हैं। यह 14 जून को भारतीय स्क्रीन पर आई और बहुत बड़ी हिट रही।

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त और सैनिकों की वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद 'महाराजा' चीन में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी। यह चार साल से अधिक समय से चल रहे सीमा गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कज़ान में अपनी बैठक में समझौते का समर्थन किया और विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने और संबंधों को सामान्य बनाने के निर्देश जारी किए, जो 2020 में गलवान घाटी में एक घातक सैन्य झड़प से प्रभावित हुए थे। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि आमिर खान की थ्री इडियट्स, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्में हाल के वर्षों में चीन में काफी सफल रही हैं, क्योंकि उनकी थीम चीनी दर्शकों को काफी पसंद आई और उन्होंने अच्छी खासी कमाई की। चीन में पूरे देश में करीब 86,000 सिनेमाघर हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीनी फिल्म समीक्षकों का कहना है कि महाराजा से भी काफी उम्मीदें हैं।

भाजपा सांसद कंगना रनौत बुधवार को नई दिल्ली में 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन परिसर जाती हुई।

यामी गौतम ने आईएफएफआई में 'आर्टिकल 370' की सफलता पर जाहिर की खुशी

पणजी/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई)में अपनी फिल्म'आर्टिकल 370' की सफलता पर खुशी जाहिर की है। यामी गौतम ने अपनी फिल्म 'आर्टिकल 370' की स्क्रीनिंग के लिए गोवा में हुए आईएफएफआई में हिस्सा लिया और फिल्म और अपने सिनेमा के सफर पर अपने विचार साझा किए। यामी गौतम ने कहा, मैंने हमेशा ऐसी फिल्मों को चुना है जो किसी न किसी तरीके से खास होती हैं, और आदित्य ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने इस फिल्म को लोकेश के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया। यह कोई बहुत पॉपुलर किस्म की फिल्म नहीं थी, और इसके साथ कई सवाल और सलाहें आईं जैसे, 'क्या आपको यकीन है? क्या ये फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी? क्या ये जुड़ पाएगी? इसमें कोई गाने नहीं हैं। यह एक गंभीर फिल्म है और डॉक्यूमेंट्री पर आधारित है।' लेकिन हमें पूरी तरह से यकीन थे कि अगर यह फिल्म अच्छी तरह से बनाई गई है, अच्छी कहानी है, अच्छे परफॉर्मेंस हैं और सही टीम का समर्थन है, तो यह जरूर सफल होगी। यामी ने कहा कि उन्होंने हमेशा मजबूत किरदारों को चुनने का फैसला जानबूझकर किया है, और हम भी इस बात से सहमत हैं। उन्होंने पर्दे पर मजबूत महिला किरदारों को बखूबी निभाया है, जो हमेशा अलग नजर आते हैं। आर्टिकल 370 उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इस साल की एक महत्वपूर्ण फिल्म बन गई है। यामी ने कहा, दोनों तरीकों से, यह एक सोचा-समझा फैसला है। मुझे लगता है कि अगर आप लगातार इस दिशा में काम करते हैं, तो दर्शक, फिल्म निर्माता, लेखक, और प्रोड्यूसर समझते हैं कि आप कॉमेडी, राजनीतिक थ्रिलर, और ड्रामा भी कर सकते हैं।

यामी ने बताया कि वह अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को कैसे बैलेंस करती हैं, और यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में उनका वर्क लोड बढ़ गया है। यामी ने कहा, असल में, मैं पहले से ज्यादा बिजी हूं, और मैं अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को बैलेंस करने के लिए तैयार हूं। यह एक बड़ा बदलाव है, लेकिन बदलाव एक रात में नहीं आता। इसके लिए बलिदान, लगातार मेहनत और बहुत से लोगों का समर्थन चाहिए। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, और मुझे इस समय सिनेमा का हिस्सा बनकर खुशी है।

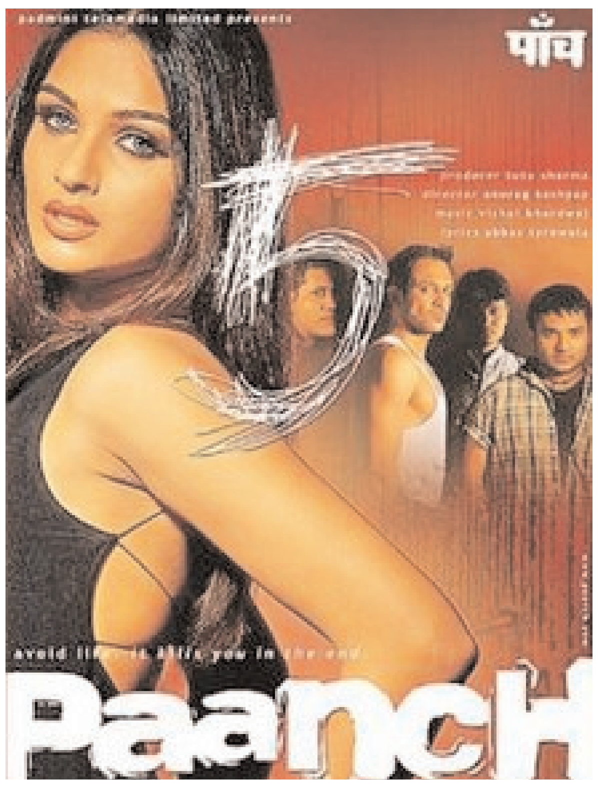

22 साल बाद रिलीज होगी अनुराग कश्यप की पहली फिल्म 'पांच'

मुंबई/एजेन्सी

निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप की पहली फिल्म को उनकी फिल्म निर्माण शैली और सिनेमा के चाहने वाले लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन अब, वे आखिरकार इसे देख पाएंगे। निर्माता टूटू शर्मा के अनुसार, 2025 में यह फिल्म रिलीज़ होगी। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में उन्होंने पुष्टि की कि पांच को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा। शर्मा ने कहा, पांच निश्चित रूप से अगले साल आ रही है। मैं इसे छह महीने के भीतर सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की योजना बना रहा हूं। फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इसके नेगेटिव थोड़े खराब हो गए हैं। उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही यह तैयार हो जाएगी, हम पांच को रिलीज़ करेंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के साथ पहले के विवाद सुलझ गए हैं, लेकिन अतिरिक्त चुनौतियों के कारण फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उन्होंने फिल्म की संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त की, उन्होंने दोबारा दिखाए जाने के मौजूदा चलन और ऐसी फिल्मों के लिए ग्रहणशील दर्शकों का हवाला दिया।

उन्होंने यह भी कहा, सिर्फ के के मेनन ही नहीं बल्कि तेजस्विनी कोल्हापुरी भी फिल्म में शानदार हैं। मेरे हिसाब से यह अनुराग कश्यप की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। कई लोग ऐसा मानते हैं। एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। के के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य, जॉय फर्नांडिस और तेजस्विनी कोल्हापुरी अभिनीत, पांच पुणे में 1976-77 में हुई जोशी-अभयंकर की सिलसिलेवार हत्याओं पर आधारित है।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ 'महावतार नरसिम्हा' का प्रीमियर

पणजी/एजेन्सी

एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा का 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में सोमवार को वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित, फिल्म महावतार नरसिम्हा भगवान विष्णु के तीसरे और चौथे अवतार-वराह और नरसिंह की महाकाव्य कथाओं को आस्था, साहस और लचीलेपन की एक आकर्षक कहानी के माध्यम से जीवंत करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुये अश्विन कुमार ने कहा, यह सिर्फ़ एक एनिमेशन फ़िल्म नहीं है, यह प्रेम का श्रम है और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति एक भेंट हैं। विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण से प्रेरणा लेते हुये, हम एक ऐसी कहानी पेश करने के लिये मूल स्रोतों के प्रति सच्चे रहे हैं, जिसकी गूंज सभी पीढ़ियों के बीच में रही है। मैं इन कहानियों को मिथकों के रूप में नहीं बल्कि हमारे सामूहिक इतिहास और चेतना के हिस्से के रूप में संरक्षित करना चाहता था। अपने जीवन के बुरे दौर में मुझे इन कहानियों से ताकत मिली। प्रह्लाद की आस्था और दृढ़ता ने मुझे यह फिल्म बनाने के लिये प्रेरित किया, मुझे उम्मीद है कि यह दूसरों के लिये भी उम्मीद की किरण बनेगी।

अश्विन कुमार ने कहा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक विरासत है। शोध और गहराई में निहित कला गहराई से प्रतिध्वनित होती है और हम अपने भविष्य के प्रयासों में इस मानक को बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, सत्य और शक्ति, आस्था और संदेह के बीच संघर्ष कालजयी रहा है। मेरा मानना ङ्क्षहै कि यह कहानी युवा दर्शकों को अपनी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। निर्माता शिल्पा धवन ने कहा, यह प्रोजेक्ट हमारी विरासत का उत्सव है। हमारा लक्ष्य इसे दुनिया भर के घरों तक पहुंचाना है, जिससे भारतीय संस्कृति की समृद्धि को सबके सामने लाया जा सके।

'पुष्पा : द रूल' के सेट को छोड़ने पर भावुक हुईं रश्मिका मंदाना

मुंबई/एजेन्सी

जल्द ही 'पुष्पा: द रूल' में नजर आने वालीं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने फिल्म के सेट पर अपने पांच साल के सफर को पूरा करने को लेकर एक नोट शेयर किया है। इस नोट में वह फिल्म के तीसरे पार्ट की ओर भी इशारा करती नजर आई। रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने चाहने वालों के साथ अपनी भावनाएं शेयर की। उन्होंने कहा कि वह बेहद ही भावुक महसूस कर रही है। उन्होंने लिखा, पूरे दिन की शूटिंग के बाद 24 तारीख की शाम को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई की उड़ान भरी। कार्यक्रम बेहद ही अच्छा था। ठीक उसी रात वापस हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। घर जाकर लगभग 4 या 5 घंटे सोई। सुबह उठकर 'पुष्पा' के अपने आखिरी दिन की शूटिंग के लिए दौड़ी। हमने एक बेहतरीन गाना शूट किया। अभिनेत्री ने बताया कि उनका पूरा दिन शूटिंग में ही बीत गया। रश्मिका ने पुष्पा 3 की ओर इशारा करते हुए कहा, 7/8 वर्षों में से, पिछले 5 साल इस सेट पर बिताने से यह मेरा घर बन गया। बेशक सेट पर आज मेरा आखिरी दिन था..मगर काम अभी भी बाकी है। अभी इसका तीसरा पार्ट भी आना है, लेकिन यह अलग लगा.. यह भारी लगा..ऐसा लगा जैसे यह खत्म हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, एक उदासी जिसे मैं भी नहीं समझ पाई, और अचानक सभी भावनाएं एक साथ आ गईं, और कड़ी मेहनत के दिन मेरे पास वापस आ गए, और मैं थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत आभारी भी थी। अभिनेत्री ने कहा कि वह टूट गई है और उन्हें समझ में नहीं आया कि वह इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रही थी। रश्मिका ने अल्लू अर्जुन, निर्देशक सुकुमार और पूरी टीम के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन और निर्देशक सुकुमार के साथ उन्होंने सालों तक काम किया। पुष्पा सेट मेरा होम ग्राउंड बन गया है और अब इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है।

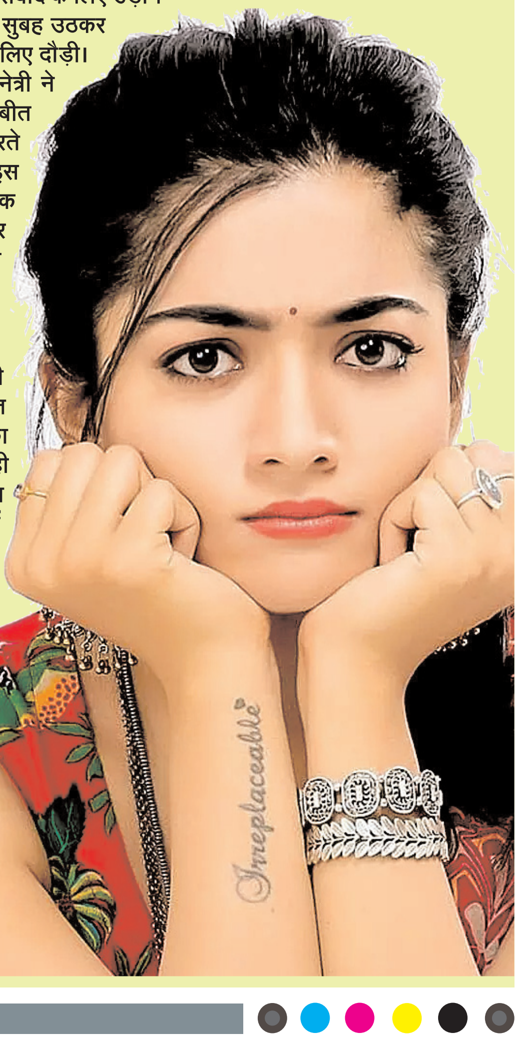

RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

जीतो जेबीएन वी-प्रेन्योर्स ने चामराजपेट स्थित जीतो कार्यालय में एक प्रेरणादायक बैठक का आयोजन किया गया॥ जीतो साउथ चैप्टर के चेयरमैन रणजीत सोलंकी ने महिलाओं के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आज की महिला उद्यमी न केवल सफल व्यवसाय चला रही हैं बल्कि मजबूत नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं।

भूमिपूजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर पालिका के विशेष अनुदान के तहत वार्ड नंबर 44 के सुभाषनगर की कंक्रीट सड़क का भूमिपूजन कार्यक्रम विधायक महेश तेंगिनकाई द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर पालिका सदस्या उमा मुकुंद और वार्ड के गणमान्य सदस्य विनोदकुमार पटवा, रघुराज इब्राहिमपुर, विनोद रेवनकर, वाईबी पाटिल आदि उपस्थित थे।

सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के मारुति मेडिकल के प्रमुख व समाजसेवी महेन्द्र मुणोत ने चाणक्य युक्कर वेदिके सुब्बणा गार्डन द्वारा अणम्मा पूजा महोत्सव में भाग लिया और अणम्मा माता की विशेष पूजा अर्चना कर मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुणोत ने अन्नदान कार्यक्रम की शुरुआत कर सेवा प्रदान की। इस मौके पर आयोजकों ने मुणोत का सम्मान किया।

इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं के लिए 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' सुनिश्चित करने का आग्रह किया

ढाका/भाषा। 'इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस' (इस्कॉन) ने बांग्लादेश सरकार से देश में हिंदुओं के लिए ''शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व'' को बढ़ावा देने का आग्रह किया और हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की हाल ही में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है।

दास को सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह एक रैली में शामिल होने के लिए चटगांव जाने वाले थे। मंगलवार को अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

दास और 18 अन्य लोगों के खिलाफ 30 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक नेता की शिकायत पर चटगांव के कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। उन पर 25 अक्टूबर को हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान शहर के लालदीघी मैदान में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। मंगलवार को एक बयान में, इस्कॉन-बांग्लादेश के महासचिव चारु चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा, ''हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और चिन्मय कृष्ण दास की हाल ही में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं... हम बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों में सनातनियों के खिलाफ हुई हिंसा और हमलों की भी निंदा करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम सरकारी अधिकारियों से सनातनियों के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का आग्रह करते हैं।''

जीतो जेबीएन वी-प्रेन्योर्स की बैठक सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जीतो जेबीएन वी-प्रेन्योर्स ने चामराजपेट स्थित जीतो कार्यालय में एक प्रेरणादायक बैठक का आयोजन किया गया।। जीतो साउथ चैप्टर के चेयरमैन रणजीत सोलंकी ने महिलाओं के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आज की महिला उद्यमी न केवल सफल व्यवसाय चला रही हैं बल्कि मजबूत नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेबीएन वी प्रेन्योर्स जैसे मंच राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि महिला उद्यमी आर्थिक वृद्धि में सक्रिय योगदान दे रही हैं। सोलंकी ने बताया कि जेबीएन वी-प्रेन्योर्स केवल व्यवसाय बढ़ाने का मंच नहीं है, बल्कि एक ऐसा समुदाय है, जहां महिलाएं एक-दूसरे को प्रेरित करती हैं, सशक्त बनाती हैं और ऊंचाइयों को हासिल करने में सहयोग करती हैं।

कल्टीवेटेड कैरेट्स की मेहक जैन ने उनकी प्रयोगशाला में निर्मित हीरों की अद्भुत दुनिया की प्रेरणादायक झलक पेश की। उन्होंने बताया कि लैब-ग्रो डायमंड्स अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके ये हीरे एक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक हीरों के गठन प्रक्रिया की नकल हैं। सदस्यों को गिफ्टिंग पार्टनर अंजलि मेहता ने सदस्याओं को उपहार दिए। बैठक की अध्यक्षता रेफरल हेड नीलम शांड, रेफरल लीड लताशा भंडारी, रेफरल सचिव ज्योति कोचेटा ने की। सभी उपस्थित सदस्याओं ने अपने व्यवसाय प्रोजेक्ट का विवरण दिया। लताशा भंडारी ने जेबीएन अचीवर्स और जेबीएन वी प्रेन्योर्स के सहयोग से 1 दिसंबर से आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट की घोषणा की, जिसमें जेबीएन वी प्रेन्योर्स की 8 सदस्य भाग लेंगी। ज्योति कोचेटा ने सभी का धन्यवाद दिया।

भंडारी पीयू कॉलेज में आयोजित हुआ अंतरकालेजीय उत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के केआर रोड स्थित सीबी भंडारी जैन पीयू कॉलेज ने अंतर्राकॉलेजीय उत्सव 'कन्फुलेन्स 2024' का आयोजन किया गया। इस उत्सव में शहर के 40 से अधिक कॉलेजों के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में संगीतकार व बैंड कलाकार अभिश्यात उपस्थित थे। अतिथि व कॉलेज के उपाध्यक्ष जी. हेमराज, विमलचन्द खांटेड़ व प्राचार्य डॉ वीणा रवि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस 'कन्फुलेन्स2024' उत्सव में विजया बाईफ्यूरिकेटेड पीयू कॉलेज ने रोलिंग ट्रॉफी जीती।

पदाधिकारियों ने विजेता कॉलेज को ट्रॉफी प्रदान की। प्राचार्या ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सम्मान

बेंगलूरु के दि न्यूज़ पेपर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक के तत्वावधान में 'कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ति 2024' सम्मान कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया गया। संस्थापक अध्यक्ष सरवन लक्ष्मण के नेतृत्व में कर्नाटक के अनेक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा करने वाले 68 व्यक्तियों का चयन कर सम्मानित किया गया। उसी श्रृंखला में व्यापार वाणिज्य एवं सेवा कार्य के क्षेत्र में प्रेम ज्वेलर्स के मुख्य राजेश चावत का भी सम्मान किया गया।

भेल ने स्थानीय आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने के लिए 'संवाद 4.0' का आयोजन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने अपने चौथे संस्करण 'भेल संवाद 4.0' का आयोजन किया। इस अवसर पर घरेलू कारोबार साझेदारों, उद्योग संघों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी संगठनों और रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों एवं एनटीपीसी, सेल, मिधानी, एचएएल आदि संस्थानों के साथ भारत मंडपम में बातचीत की। भारी उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय 'नवाचार और सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता को मजबूत करना था। भेल के स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।

अपने संबोधन में केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में देश की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं जैसी प्रमुख पहलों से प्रेरित भारत के विनिर्माण क्षेत्र के परिवर्तनकारी विकास पर प्रकाश डाला।

देश के बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने में भेल की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, उन्होंने देश के आत्मनिर्भरता एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग, नवाचार और संवाद को बढ़ावा देने वाले एक अद्वितीय मंच के रूप में संवाद की सराहना की। इस अवसर पर एचआई सचिव कामरान रिज़वी ने इस मंच के जरिए सहयोग और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए भेल की सराहना की।

उन्होंने संवाद 4.0 के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों की सामग्री की सराहना की, जिसमें एआई और साइबर सुरक्षा शामिल थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग और भेल को हर क्षेत्र में लगातार नवाचार करके मेक इन इंडिया के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखना चाहिए।

एसएलबीसी बैठक : योजनाओं के तहत पात्र जनसंख्या का पूर्ण कवरेज करने के लिए कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

केनरा बैंक Canara Bank

बेंगलूरु। 167वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) बैठक मंगलवार को विधान सौधा में हुई। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त उमा महादेवन ने की। सह-अध्यक्षता केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक हरदीप सिंह अहलूवालिया ने की। अन्य गणमान्य लोगों में कर्नाटक के वित्त विभाग (राजकोषीय सुधार) के सचिव डॉ. विशाल आर, आरबीआई की क्षेत्रीय निदेशक सोनाली सेन गुप्ता, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक केवीएसएसएलवी प्रसाद राव, एसएलबीसी कर्नाटक के संयोजक केजे श्रीकांत और सभी बैंकों के राज्य नियंत्रण प्रमुख शामिल थे। उमा महादेवन ने सभी संबंधित विभागों और बैंकर्स को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत पात्र जनसंख्या का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने की सलाह दी। उन्होंने दूसरी तिमाही के दौरान 79.97 प्रतिशत का क्रेडिट-डिपोजिट अनुपात हासिल करने के लिए बैंकर्स की सराहना की तथा उन्हें वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

हरदीप सिंह अहलूवालिया ने कहा, '79.97 प्रतिशत का सीडी अनुपात प्राप्त करने तथा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में प्रगति सराहनीय है। सभी हितधारकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए प्रयासों में तेजी लाना जरूरी है, विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला एसएचजी सदस्यों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में तैनात करने जैसे नवीन उपायों के जरिए।'

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों पर भी अद्यतन जानकारी दी, जो 30 सितंबर तक 1,04,519 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस तरह वर्ष के लिए 1,92,201 करोड़ रुपए के लक्ष्य का 54 प्रतिशत हासिल कर लिया गया। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र में प्रगति पर प्रकाश डाला, जहां 62 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया तथा कुल मिलाकर प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने का कार्य अपने लक्ष्य के 57 प्रतिशत तक पहुंच गया। उन्होंने सभी बैंकर्स से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास का आग्रह किया। हरदीप सिंह अहलूवालिया ने मुद्रा और पीएम स्वनिधि योजनाओं के तहत सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में बैंकर्स के प्रयासों की सराहना की। केजे श्रीकांत ने सबका स्वागत किया। बी पार्श्वनाथ ने बैठक का संचालन किया।

स्वागत

बुधवार को बेल्लारी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या का जिंदल हवाई अड्डे पर स्वागत संदूर निर्वाचन क्षेत्र की नई विधायक अन्नपूर्णम्मा ने किया और धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णम्मा को चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दीं।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय में मनाया संविधान दिवस

पुदुचेरी। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पांडिचेरी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम विधि विद्यालय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डीन(प्रभारी) प्रो. विक्टर आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरमिंदर कौर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर पुदुचेरी सरकार के सचिव (विधि) डॉ. एलएस सत्यमूर्ति उपस्थित थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. थारानिक्करासु ने की। डॉ. सत्यमूर्ति ने संविधान द्वारा भारत में सुशासन सुनिश्चित करने में निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराते हुए सुशासन के संवैधानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

विकसित भारत का सपना विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की धुरी पर टिका है: संयुक्त राष्ट्र

नई दिल्ली/भाषा। परिवर्तन के वाहक के रूप में भारत के विद्यार्थियों की विपुल क्षमता का उल्लेख करते हुए देश में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक शोम्बी शार्प ने कहा है कि 'विकसित भारत' का सपना यह सुनिश्चित करने पर टिका है कि विद्यालय में बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बल्कि उन्हें 'कल के जिम्मेदार आदर्श नागरिक' बनने के लिए भी संवेदनशील बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने बुधवार को अपनी 'राइजअप4पीस' शैक्षिक पहल पर एक बयान जारी किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को 'नकारात्मक प्रभावों, उभरती कमजोरियों और जोखिमपूर्ण आचरणों से अपने आपको बचाने' के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना है। बयान के अनुसार देश में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक ने ''बदलाव के वाहक के तौर पर भारत के 26.52 करोड़ विद्यार्थियों की विपुल क्षमता' का उल्लेख किया तथा समावेशी एवं शांतिप्रिय समाज के वास्ते मूल्यों पर आधारित गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के महत्व पर बल दिया। बयान के मुताबिक उन्होंने कहा, '' प्रधानमंत्री ने जिस विकसित भारत का सपना देखा है, वह यह सुनिश्चित करने पर टिका है कि विद्यालय में बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बल्कि उन्हें 'कल के जिम्मेदार आदर्श नागरिक' बनने के लिए भी संवेदनशील बनाया जाए। यूएनओडीसी ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप, 2023 दोनों ही ऐसे जिम्मेदार नागरिक के रूप में लोगों को तराशने की जरूरत को महत्व देते हैं जो लगातार जटिल हो रही दुनिया में वे शांति एवं सद्भाव में योगदान दे सकें, लेकिन इस महत्वाकांक्षा के वास्ते शिक्षा के पारंपरिक दायरे से आगे जाना होगा - इसके लिए 'कक्षाओं, स्कूलों और समुदायों में शैक्षिक हस्तक्षेप की पुनःकल्पना की जरूरत है।

मुलाकात

बेंगलूरु में बुधवार को चन्नपट्टना निर्वाचन क्षेत्र के नए विधायक सीपी योगेश्वर से मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें चन्नपट्टना क्षेत्र से चुनाव जीतने पर बधाई दी।

अभिनेता दर्शन ने अदालत में रेणुकास्वामी को 'समाज के लिए खतरा' बताया

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में दलील दी कि रेणुकास्वामी 'समाज के लिए खतरा' था। दर्शन का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील सी वी नागेश ने अभिनेता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह बयान दिया। नागेश के अनुसार रेणुकास्वामी का महिलाओं की अश्लील तस्वीरें साझा करने की इतिहास था, उसके मन में सामाजिक नियमों या महिलाओं के लिए सम्मान का कोई भाव नहीं था। नागेश ने कहा कि उसका आचरण निंदनीय था। नागेश ने कहा, '' महिलाओं के प्रति सम्मान तथा कानून के प्रति निष्ठा का कोई भाव नहीं रखने वाले व्यक्ति को अब राष्ट्रीय नायक के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि सुनहरे पर्दे पर नायक मेरे मुवक्किल को खलनायक के रूप में अपमानित किया जा रहा है।''

वकील ने जांच में कथित प्रक्रियागत खामियों का भी उल्लेख किया जिनमें शव के संबंध में गहन जांच एवं पोस्टमार्टम परीक्षण में देरी शामिल हैं। नौ जून को एक सुरक्षागार्ड को रेणुकास्वामी के शव का पता चला था। नागेश ने इस दावे का भी खंडन किया कि दर्शन के आदेश पर रेणुकास्वामी का अपहरण किया गया। उन्होंने कहा कि रेणुकास्वामी अपनी मर्जी से चित्रदुर्ग से बेंगलुरु गया था। न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी 28 नवंबर को भी दर्शन की नियमित जमानत अर्जी पर दलीलें सुनेंगे।

पुलिस के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गये थे फलस्वरूप कथित तौर पर उसकी (रेणुकास्वामी की) हत्या कर दी गई। रेणुकास्वामी का शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को यहां आर आर नगर में एक शेड में इस बहाने से बुलाया था कि अभिनेता उससे मिलना चाहते हैं। आरोप है कि इसी शेड में उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। राघवेंद्र चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग के मूल निवासी रेणुकास्वामी की मौत कई चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई।

पुलिस ने पवित्रा को 'आरोपी नंबर एक' बताते हुए कहा कि वह रेणुकास्वामी की हत्या की 'मुख्य वजह' थी। पुलिस ने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि पवित्रा ने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और वारदात में भाग लिया। दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य इस मामले में सह-आरोपी हैं। दर्शन फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com